● वर्ष : 17 ● अंक : 108 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित गुरुवार 5 फरवरी 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

पीएम का तय था भाषण, फिर भी स्थगित हुई लोकसभा; हंगामे से बिगड़ा माहौल

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आज (बुधवार, 4 फरवरी को) शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले थे लेकिन उनका संबोधन नहीं हो सका। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद आखिरकार शाम पांच बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष का कहना है कि यदि नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा तो पीएम मोदी को भी भाषण देने नहीं दिया जाएगा। इस मामले को लेकर अब गुरुवार को भी जमकर बवाल हो सकता है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या प्रधानमंत्री गुरुवार को सदन में अपना संबोधन देंगे? बता दें कि इससे पहले दिन में तीन बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी। शाम पांच बजे जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर वेल में आ गए और जोरदार हंगामा करने लगे। इसे देखते हुए पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

पिछले तीन दिनों से हंगामा : दरअसल, लोकसभा में पिछले तीन दिनों से हंगामा हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को डोकलाम मुद्दे पर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के एक संस्मरण का उल्लेख करना चाहा तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और अप्रकाशित किताब का उल्लेख करने से रोक दिया। आसन ने भी ऐसी ही व्यवस्था दी। इस पर पिछले तीन दिनों से सदन में गतिरोध बना हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी उसी बात पर अड़े हुए हैं। विपक्षी दलों के भी सांसदों ने कल राहुल का समर्थन करते हुए सदन में चर्चा में भाग लेने से परहेज किया।

निशिकांत दुबे ने दिखाईं किताबें : बुधवार को सदन में हालात तब बिगड़ गए, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी पलटवार करते हुए सदन में किताबें दिखाईं। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने आज भी आसन पर कागज के टुकड़े फेंके। हंगामे के कारण पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने सदन की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी और अब उसे कल तक स्थगित कर दिया गया

राष्ट्रपति का अभिभाषण परंपरा और प्रगति का संगम : जेपी नड्डा

नई दिल्ली। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर बुधवार को चर्चा जारी रखते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का ज़िक्र कर उन्होंने कहा कि सरकार इसपर भी चर्चा के लिए तैयार है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अस्वस्थ होने के बावजूद मुंबई से दिल्ली आए, ताकि लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान दे सकें लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाने के कारण उनका भाषण नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि भारत–अमेरिका व्यापार समझौता संतुलित है और देशहित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का नजरिया संकीर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत की परंपराओं के साथ-साथ विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप पेश करता है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की अद्भुत विकास यात्रा का शक्तिशाली प्रतिबिंब हमें देखने को मिला है। हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के साथ ही वर्ष-2047 के विकसित भारत का समावेश राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है। उन्होंने कहा कि देश ने लंबा सफर तय किया है और प्रगति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम पहले किस स्थिति में थे। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत कभी "फ्रैजाइल फाइव" देशों में गिना जाता था, लेकिन आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश नीतिगत जड़ता (पॉलिसी पैरालिसिस) से निकलकर अब रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पहले जहां देश घोटालों के लिए जाना जाता था, वहीं अब पारदर्शिता की क्रांति देखने को मिल रही है।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

अमेरिका की भारत के साथ सशर्त ट्रेड डील

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील की पेशकश करके वैश्विक व्यापार पर हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने भारत पर लगाए गए पारंपरिक टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही कहा गया है कि कुछ उत्पादों पर शून्य टैरिफ लागू किया जा सकता है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से उत्पाद इसमें शामिल होंगे। इस तरह एक प्रकार से ट्रंप ने भारत सरकार को एक लॉलीपॉप दिया है, कि वह भारत के टैरिफ को शून्य कर देंगे। बहरहाल इस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने राहत जताई है, क्योंकि पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच टैरिफ़ मुद्दे पर तनाव बना हुआ था। हालांकि, इस प्रस्ताव में कई जटिलताएं भी हैं।

अमेरिका ने भारत से अगले 20 वर्षों में 500 अरब डॉलर के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 46 लाख करोड़ रुपए होता है। यह लक्ष्य भारत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत रूस और ईरान से तेल नहीं खरीदेगा और उसकी जगह वेनेज़ुएला से तेल की खरीदी करेगा। इसके साथ ही कृषि और डेयरी उत्पादों में अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रस्ताव से भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों को गंभीर चिंता है। यदि अनाज, गेहूं, मक्का, डेयरी उत्पाद और अन्य प्रमुख कृषि उत्पाद अमेरिका से शून्य ड्यूटी पर आयात होते हैं, तो इससे घरेलू किसानों और डेयरी उत्पादकों को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका के डेयरी उत्पादों में गायों और अन्य जानवरों को मांसाहारी भोजन दिया जाता है, जो धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भारत में स्वीकार्य नहीं है। यही कारण था कि भारत सरकार अनाज और डेरी उत्पाद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी बाजार को खोलने का सख्त विरोध करता रहा है। ऐसे में यह समझौता भारतीय किसानों के हितों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इस पेशकश से भारतीय शेयर बाजार को नई ऊर्जा मिली है। मंगलवार को शेयर बाजार मे रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार लगभग 2500 अंको की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ। अडानी और रिलायंस के शेयरों में भारी बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा शेयर बाजार में हीरा, सोना, मशीनरी, स्टील, अल्युमिनियम, कॉपर, टेक्सटाइल और केमिकल कंपनियों के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यह दर्शाता है कि निवेशक इस कदम को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं। यही नहीं इस डील से भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका की इस डील के बाद रूस और ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध लग जाएगा, जबकि यूरोपीय संघ और चीन के साथ भारत के व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

राहुल गांधी ने संसद परिसर में नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक दिखलाते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा

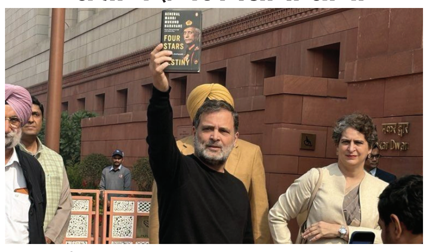

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद के बाहर पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक दिखलाते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कथित तौर पर चीन के साथ साल 2020 में सैन्य तनातनी के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर पुस्तक में दिए विवरण को आधार बनाया और सरकार पर मुश्किल समय में सेना का साथ छोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी संसद के मकर द्वार के बाहर नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक की प्रति दिखलते हुए कहा कि भारत के हर युवा को यह किताब देखनी चाहिए। इसमें उन्होंने लद्दाख का पूरा ब्योरा दिया है। लोकसभा में उन्हें इसी किताब में कही बातों को रखने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कल पत्र लिखकर संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा उठाने के विपक्ष के नेता के अधिकार से वंचित किए जाने के संबंध में अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा कि भाषण देते समय वे अक्सर पुस्तकों से उद्धरण देते हैं।

संसद परिसर में तीखी जुबानी जंगः राहुल गांधी ने बिट्टू को कहा 'गद्दार दोस्त'

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को संसद परिसर उस समय राजनीतिक अखाड़ा बन गया, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। यह पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी हलकों में हलचल मच गई। घटना उस वक्त हुई जब कांग्रेस सांसद निलंबित सदस्यों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी उनके साथ खड़े नजर आए। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राहुल गांधी ने बिट्टू की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये रहा गद्दार, इसका चेहरा देखो।" यहीं नहीं, राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "हैलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त... चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे।" राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर रवनीत सिंह बिट्टू भड़क उठे। उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार करते हुए पलटवार किया और कहा, "देश के दुश्मन...।" इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बहस होती रही, जिससे संसद परिसर का माहौल और गरमा गया। गौरतलब है कि रवनीत सिंह बिट्टू कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को पुराने रिश्तों और दल-बदल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

बंगाल में ही क्यों, असम में क्यों नहीं हुआ एसआईआरः सीएम ममता

एजेंसी। नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव 2026 होने हैं, वहां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच, सीएम ममता बनर्जी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एसआईआर मामले की सुनवाई की। इस संबंध में सीएम कोर्ट के सामने पेश हुईं। सुनवाई से पहले सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर से सुप्रीम कोर्ट के लिए निकलीं। सुप्रीम कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तमिलनाडु में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान लॉजिकल डिस्क्रपेंसी लिस्ट में कैटेगरी में आए वोटर्स के नाम पब्लिश करने का निर्देश दिया था। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने तमिलनाडु में एसआईआर प्रोसेस को प्रोसेस में गड़बड़ी के आधार पर चुनौती देने वाली कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद रहीं। उन्होंने अपना केस लड़ने और बहस करने की इजाजत मांगी थी। सीजेआई ने ममता से कहा कि वे अपने वकील को मामले पर बहस करने दें और जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। बेंच ने कहा कि वह सोमवार को मामले पर फिर से सुनवाई करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ममता का कहना है कि वे माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त करके सिर्फ बंगाल को निशाना बना रहे हैं।

मणिपुर से हटा राष्ट्रपति शासन, खेमचंद सिंह के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मणिपुर में पिछले 1 साल से जारी राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। इसके साथ ही राज्य में फिर से भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुबंध 2 के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर राज्य से जुड़ी घोषणा को वापस ले लिया है। दिल्ली में एकदिन पूर्व मंगलवार को युमनाम खेमचंद सिंह को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके नेतृत्व में आज राजग के वरिष्ठ नेताओं ने मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की और भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के सरकार गठन के लिए समर्थन पत्र सौंपा। दिल्ली में पार्टी विधायकों की बैठक के बाद भाजपा नेता सिंह को नेता चुना गया। बाद में केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ ने पारंपरिक पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष अधिकारिमयूम शारदा देवी और पूर्वोत्तर के प्रभारी संबित पात्रा भी मौजूद रहे। भाजपा विधायक युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले साल फरवरी में जातीय हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और बाद में इसे छह माह आगे बढ़ाया गया था। राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष में हजारों लोग विस्थापित और सैकड़ों लोग मारे गए थे। उल्लेखनीय है कि मणिपुर की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले अनुभवी राजनेता युमनाम खेमचंद सिंह इंफाल पश्चिम जिले की सिंगजामेई सीट से दो बार मणिपुर विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की।

डिप्टी सीएम के बाद अब सुनेत्रा पवार बन सकती हैं एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष

मुंबई। महाराष्ट्र में एनसीपी में सुनेत्रा पवार की ताकत और बढ़ सकती है। पति अजित पवार के निधन के बाद वह डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। अब वह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने की तैयारी में हैं। बता दें अजित पवार की बीते सप्ताह एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। इसके तीन दिन बाद ही सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। फिर चर्चा थी कि प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब यह पद भी सुनेत्रा पवार को ही मिल सकता है। प्रफुल्ल पटेल ने खुद को अध्यक्ष बनाए जाने के कयासों को खारिज कर दिया है और कहा कि पार्टी के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार ही अध्यक्ष बनें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी सुनेत्रा पवार का कद बढ़ा दिया है। उन्हें पुणे और बीड जिलों का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है। अजित पवार के पास भी इन जिलों की जिम्मेदारी थी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार ही अध्यक्ष बनें और सभी लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करने में उनकी मदद करेंगे। यह अजित पवार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही नहीं उन्होंने कहा कि हम पार्टी की एक बैइक बुलाएंगे और उसमें फैसला लेंगे।

ट्रेड डील से अमेरिका ने भारत को खरीद लिया, अब किसान क्या आत्महत्या करेगा

एजेंसी। नई दिल्ली

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस डील के तहत अमेरिका ने भारत को खरीद लिया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि सरकार के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर लगाए टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने बुधवार को कहा कि पीयूष गोयल समेत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो ट्रेड डील हुई है, वो हमारा देश लगभग अमेरिका के चरणों में डाल दिया है। अमेरिका ने हमको खरीद लिया है। बोलते हैं कि यह बहुत बड़ी हमारी विजय है। कौनसी विजय है भाई। आप बताइये। आप पूरे देश में जश्न मनाने की बात करते हो। उन्होंने कहा कि भारत को आज भी भारी टैरिफ देना पड़ रहा है। राउत ने कहा कि 18 फीसदी टैरिफ आज भी कायम है, जो पहले 3 फीसदी था। उसके बावजूद अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं, वो जीरो टैरिफ पर भारत के बाजार में आ जाएंगे, जिसमें सभी धान, फल, फूल, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे।

विपक्ष के हंगामे के बीच पीयूष गोयल ने लोकसभा में भारत-अमेरिका व्यापार डील पर दिया बयान

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच भारत-अमेरिका के बीच व्यापार डील पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश और निर्यातकों के हित में है और इसमें कृषि-खाद्य क्षेत्रों की संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के भारी शोर-शराबे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। गोयल के बयान के दौरान लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ जिस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहा है, वह संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है। उन्होंने सदन को बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए बातचीत पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते से भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। गोयल ने लोकसभा में कहा कि दोनों देश जल्द ही समझौते का विवरण देते हुए एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि इस डील में उर्वरक और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि यह समझौता छोटे और मध्यम कारोबारियों, एमएसएमई, औद्योगिक इकाइयों, कुशल श्रमिकों और उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा एवं उन्नत तकनीकों तक पहुंच को आसान बनाएगा। इससे 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड', 'डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' और 'इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्यों को गति मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के हितों को देखते हुए स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे।

टैरिफ घटते ही उड़ी चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश की नींद, अब दुनिया में छाएंगे भारत के उत्पाद

वॉशिंगटन । वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर लगने वाले भारी-भरकम 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर अब सीधे 18 प्रतिशत कर दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा अर्थ यह है कि अब अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान पहले की तुलना में काफी सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। इस कटौती के बाद भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और अन्य प्रमुख एशियाई निर्यातक देशों की तुलना में काफी लाभप्रद स्थिति में आ गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान को वर्तमान में अमेरिकी निर्यात पर 19 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ रहा है, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए यह दर 20 प्रतिशत पर टिकी हुई है। हालांकि अफगानिस्तान के लिए यह दर 15 प्रतिशत है, लेकिन उसकी सीमित उत्पादन क्षमता के कारण भारत को वहां से किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों जैसे वियतनाम (20 प्रतिशत), इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड (सभी 19 प्रतिशत) के मुकाबले भी भारत अब बढ़त बनाने में सफल रहा है। यह महत्वपूर्ण बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 2 फरवरी को हुई एक उच्च स्तरीय फोन कॉल के बाद देखने को मिला है। इस बातचीत के तुरंत बाद ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका भारत पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर रहा है। इसके बदले में भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाली अपनी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने पर सहमत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सबसे गहरा असर चीन और भारत के पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। चीन से अमेरिका जाने वाले सामानों पर फिलहाल 34 प्रतिशत का भारी टैरिफ लागू है, जो भारत की नई दर के मुकाबले लगभग दोगुना है।

तेलंगाना के मेदाराम जातरा में कथित यौन उत्पीड़न पर एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, जांच समिति गठित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम में हाल ही में आयोजित सम्मक्का–सरलम्मा जातरा के दौरान 13 वर्षीय बालिका के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना का संज्ञान लिया है। यह घटना छत्तीसगढ़ के पांच युवकों द्वारा कथित रूप से किए गए सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस कथित घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। आयोग द्वारा बुधवार को जारी जानकारी के अनुसार जांच समिति की अध्यक्षता एनसीडब्ल्यू की सदस्य डेलिना खोंगदुप करेंगी। एनसीडब्ल्यू की वरिष्ठ समन्वयक कंचन खट्टर समिति की सदस्य होंगी। समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), मुलुगु, तेलंगाना द्वारा नामित एक अधिवक्ता की सहायता भी ले सकती है।समिति जांच की शुरुआत 5 फरवरी से करेगी। समिति के सदस्य कथित घटना तक पहुंचने वाली परिस्थितियों की जांच, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन, तथ्यों की पुष्टि हेतु संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों से संवाद करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों की संस्तुति करने का दायित्व सौंपा गया है।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

अनिल अंबानी के खिलाफ जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई-ईडी को फटकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके पूर्व प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़े कथित हजारों करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच में देरी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच एजेंसियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि अनिल अंबानी देश से बाहर न जाएं। अनिल अंबानी ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वो बिना अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने 23 जनवरी को अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े बड़े बैंक धोखाधड़ी की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है और सीबीआई और ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जांच एजेंसियां बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी और उनके अफसरों की इस मामले में संलिप्तता की जांच नहीं कर रही हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला देश के इतिहास में शायद सबसे बड़ा कारपोरेट धोखाधड़ी है। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि एफआईआर 2025 में दर्ज की गई थी, जबकि धोखाधड़ी 2007-08 से चल रही थी। याचिका में सार्वजनिक धन की साजिशन हेराफेरी और इस हेराफेरी में अनिल अंबानी की कंपनियों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं के लंबित होने पर चिंता जताई

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं के लंबित रहने पर निराशा जताई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये बहुत दुखद है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले पर भी देरी से सुनवाई की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से लंबित अग्रिम और नियमित जमानत याचिकाओं की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस से उम्मीद जताई कि जमानत याचिकाओं को तय समय में निपटारे के लिए योजना बनाएं। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि पटना उच्च न्यायालय में इस बात के लिए याचिकाएं दायर की जा रही हैं कि जमानत याचिकाएं लिस्ट नहीं की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि जमानत याचिकाओं के जल्द निस्तारण के उच्चतम न्यायालय के आदेश का कोई असल प्रभाव नहीं दिख रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय को दिशा-निर्देश जारी करना पड़ सकता है। मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है, जहां जमानत याचिकाओं के काफी समय से लंबित होने की शिकायतें हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को कुछ चार्ट दिखाए और बताया कि मई, 2025 से जमानत याचिकाओं पर कई बार सुनवाई टाली गई।

रजत शर्मा के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश और रागिनी नायक को समन

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा की आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को नोटिस जारी किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देवांशी जनमेजा ने तीनों कांग्रेस नेताओं को 27 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, पत्रकार रजत शर्मा ने याचिका दायर कर कहा है कि 4 जून, 2024 को न्यूज चैनल पर एक शो के दौरान कथित रुप से कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने अपने ट्विटर हैंडल पर रजत शर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने शो के दौरान रागिनी नायक को गाली दी। 4 जून, 2024 के शो को लेकर ये आरोप रागिनी नायक ने 10 जून, 2024 को अपने एक्स हैंडल पर आरोप लगाया कि रजत शर्मा ने उन्हें गाली दी। 4 जून का शो 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान का था। रजत शर्मा की याचिका में कहा गया है कि न्यूज चैनल पर शो के 6 दिन बाद रागिनी नायक ने जानबूझकर रजत शर्मा के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए ट्वीट किया। उस ट्वीट को कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। ऐसा कर रागिनी नायक और दोनों कांग्रेस नेताओं ने रजत शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की। रजत शर्मा ने इन आरोपों को मानहानि वाला बताया है। याचिका में कहा गया है कि रजत शर्मा पिछले 40 सालों से ज्यादा से पत्रकारिता में हैं और वे अपने सभ्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने टीवी स्क्रीन पर कभी भी किसी पर चिल्लाकर भी बात नहीं की। कांग्रेस नेता रागिनी नायक को भी छह दिन बाद तब पता चला है जब उनके किसी फॉलोवर ने उसे सुना होगा। उसके बाद जानबूझकर रजत शर्मा को बदनाम करने के लिए गाली वाला वीडियो ट्वीट में डाला गया। उसके बाद इंडिया टीवी ने रागिनी नायक और कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को टैग करते हुए सार्वजनिक रुप से कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वे झूठे और बेबुनियाद हैं। इंडिया टीवी ने कहा था कि ये आरोप मानहानि वाले हैं और वे फेक न्यूज की श्रेणी में आते हैं।

रवनीत सिंह बिट्टू को 'देशद्रोही' कहे जाने पर भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को "देशद्रोही" कहे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए उन्हें सिख विरोधी बताया। भाजपा मुख्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि "देशद्रोही" जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए क्योंकि इसका मतलब देश से गद्दारी करने वाले व्यक्ति से होता है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिख समुदाय से भी जुड़ा है और राहुल गांधी का ऐसा बयान बेहद गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि रवनीत बिट्टू ने उनकी पार्टी छोड़ दी। राहुल गांधी ने बिट्टू से यह भी कहा था कि वे वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि पगड़ी पहनने वाला कोई व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़ दे, उसे देशद्रोही कहना बिल्कुल गलत और अस्वीकार्य है।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति को इस तरह का लेबल देना न तो सही है और न ही स्वीकार्य। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि संसद के भीतर और बाहर, राजनीतिक संवाद की भाषा शालीन और मर्यादित होनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है लेकिन भाषा की गरिमा बनाए रखना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। उधर, संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के 'गद्दार' कहे जाने का जवाब देते कहा कि "कांग्रेस और गांधी परिवार ने पंजाब में आग लगाई थी। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर पर गोलियां चलाई गईं। हज़ारों सिखों और पंजाबियों को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई। अगर राजीव गांधी को 'शहीद' कहा जाता है तो हमें शहीद-ए-आज़म सरदार बेअंत सिंह को भी शहीद कहना चाहिए। मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, यह मेरा दर्द है।" उन्होंने कहा कि "एक शहीद का पोता तब तक ठीक था, जब तक मैं उनके साथ था। अब जब मैं भाजपा में हूँ तो वह मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह अपने आप को क्या समझते हैं? उन्होंने मेरी ओर ऐसे हाथ बढ़ाया, जैसे वो कोई शहंशाह हों। वह खुद को इस देश का, इस दुनिया का मालिक समझते हैं।" उन्होंने कहा को वे गांधी परिवार से नहीं है लेकिन मेरे सिर पर पगड़ी है। इसलिए जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश की तो मैंने कहा, 'आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो।'

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को आज ही सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव को निर्देश दिया कि उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करने का आदेश तब दिया गया था, जब राजपाल यादव ने कोर्ट को दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं किया। ऐसे में अब सरेंडर करने के लिए समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद राजपाल यादव ने सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि जून, 2024 में उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं, इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है। दरअसल, कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर 1.60 करोड़ का जुर्माना लगाया था।

कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था। दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी। शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल ने अप्रैल, 2010 में फिल्म अता पता लापता पूरी करने के लिए कंपनी से मदद मांगी थी। 30 मई, 2010 में दोनों के बीच करार हुआ और उन्होंने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ का लोन दे दिया। करार के मुताबिक राजपाल को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपए लौटाने थे। लेकिन वह पहली बार ये रकम नहीं लौटा सके। उसके बाद दोनों के बीच तीन बार करार का रिनिवल हुआ। 9 अगस्त, 2012 को वह अंतिम करार में आरोपी राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता को 11 करोड़ 10 लाख 60 हजार 350 रुपए लौट आने की सहमति भी थी। राजपाल यादव की कंपनी यह भी पैसा देने में नाकाम रही। अपने बचाव में राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से कोई उधार नहीं लिया था। राजपाल यादव के मुताबिक मुरली प्रोजेक्ट की कंपनी में पैसा निवेश किया था। लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें चेक बाउंस का दोषी पाया था।

दिल्ली सरकार 11 वर्षों की समस्याओं को जड़ से खत्म कर रही है : सिरसा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट से शहर के विकास को और गति मिलेगी। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों की समस्याओं को जड़ से खत्म करने लिए दिन-रात काम कर रही है। मंत्री सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में राजधानी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की पब्लिक बॉरोइंग की सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब हमें बाजार से 21,000 करोड़ रुपये जुटाने की क्षमता मिली है। इससे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और शहर के विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट में दिल्ली को बहुत राहत दी है, इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री सिरसा ने कहा कि यह बजट हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करने वाला, उसको सशक्त करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के साथ-साथ विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध पर मंत्री सिरसा ने कहा कि उन्हें अपने देश के लोगों से ज्यादा बांग्लादेश से प्यार हैं और वोटों के लिए ऐसा करने उचित नहीं है।

खरगे बोले- भारत-अमेरिका ट्रेड डील से भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे, ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे मोदी

लोकतंत्र की शान , संवाददाता जीशान अली

नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को भारतीय किसानों को बर्बाद करने वाला बताते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुटने टेक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संसद सत्र के समय इस डील की जानकारी सांसदों को भारत सरकार से नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिली, ये संसद का अपमान है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस डील से अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के विशाल बाजार में ज्यादा निर्यात होंगे और ग्रामीण अमेरिका में नकदी जाएगी। खरगे ने कहा कि भारत के किसान भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी उत्पादों से कैसे मुकाबला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस डील को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि कृषि आयात बढ़ने से एमएसपी प्रणाली पर दबाव पड़ेगा। बिना तैयारी के करोड़ों भारतीय किसानों को संपन्न अमेरिकी किसानों के सामने खड़ा कर दिया गया। इस डील से किसानों को कुचलने की तैयारी की जा रही है। विफल विदेश नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए खरगे ने कहा कि ट्रंप बार-बार भारत को अपमानित कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है

कि उन्होंने ट्रेड धमकी से भारत-पाक युद्ध रोका और मोदी ने उन्हें खुश करने के लिए रूसी तेल आयात घटाया। अब ट्रंप घोषणा करते हैं कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। चीन को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले 'लाल आंख' दिखाने वाले आज चीन के लिए ट्रेड का रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, जबकि गलवान के बाद चीन लद्दाख-अरुणाचल पर दावा कर रहा है। वह भारत के साथ आर्थिक रिश्ते अपनी शर्तों पर तय कर रहा है। उन्होंने इसे स्ट्रैटेजिक सरेंडर बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी सरकार चुप है।

सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए किताब रिलीज

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज देश की शासन प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और संविधान के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली किताब 'इंडियन पॉलिटी' को रिलीज किया। यह किताब भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी वाई. कुमार द्वारा लिखी गई है और उनका दावा है कि यह उनके दशकों के प्रशासनिक अनुभव और बरसों के लेखन का परिणाम है। उन्होंने इस किताब को विभिन्न सिविल परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिखी है। कॉम्पिटिशन बुक हाउस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के प्रकाशक लोकेश थानी ने बताया कि यह किताब संविधान के गहन अध्ययन के बाद सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले युवाओं को आसान भाषा में भारतीय संविधान, शासन और सामाजिक न्याय की विस्तार से जानकारी देती है। किताब के दो संस्करण हैं लेकिन अभी एक संस्करण के साथ दूसरा बिना किसी

अतिरिक्त मूल्य के दिया जा रहा है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान के विरोध में किया प्रदर्शन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर दिए गए बयान के विरोध में किया गया। प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने केवल एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरे सिख समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सिख विरोधी रहा है और 1984 के दंगों के दौरान भी कांग्रेस ने सिखों को गद्दार कहा था। सचदेवा ने आरोप लगाया कि आज भी कांग्रेस की सोच वही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस कौम को गाली दी है जिसने देश के लिए शहादत का कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की। उल्लेखनीय है कि, संसद परिसर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद यह राजनीतिक विवाद हुआ।

डीयू में "एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ साइंसेज" ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बुधवार को चिकित्सा क्षेत्र में एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर "एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ साइंसेज" नाम से ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि भविष्य में टेक्नोलोजी ओरिएंटेड़ डॉक्टरों की जरूरत है, इसलिए ऐसे कोर्स होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन के साथ-साथ ऐसे वीकेंड ऑफ लाइन कोर्स भी शुरू किए जाने चाहियें। कुलपति ने कहा कि जैसे कंप्यूटर आने पर लोगों को काम छीनने की चिंता हुई थी, वैसे ही एआई को लेकर कुछ लोग चिंता करते हैं कि यह रोजगार छीन लेगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इसके साथ बहुत से रोजगार

विकसित होंगे, पूरी तरह से एआई पर निर्भर नहीं हो सकते। मानवीय कार्यों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि मशीन में समझ तो आ सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं इसीलिए सभी कार्य मशीन आधारित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। इस अवसर पर डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी, डीन अकादमिक प्रो. के. रत्नाबली, डीयू की रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के चेयरपर्सन प्रो. दिनाबंधु साहू, कोर्स डायरेक्टर प्रो. दमन सलूजा, कोर्स जॉइंट डायरेक्टर प्रो. नवीन कुमार और कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉ. अंकित राजपाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि डीयू की रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के तत्वावधान में चलाया जाने वाला यह कोर्स आठ मॉड्यूल में होगा। यह कोर्स सौ प्रतिशत ऑनलाइन मोड में होगा, जिसकी अवधि 15 सप्ताह (शनिवार और रविवार, हर दिन 2 घंटे) होगी। कोर्स में प्रति बैच 50 सीटें रखी गई हैं। कोर्स के लिए अनिवार्य योग्यता सीएस, आईटी, इंजीनियरिंग, गणित, सांख्यिकी या लाइफ साइंसेज एवं हेल्थकेयर (एमबीबीएस, नर्सिंग, फार्मेसी) में बैचलर है। इस कोर्स का प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य विज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों में व्यापक आधार प्रदान करना है, जिससे प्रतिभागियों को मेडिकल एआई सिस्टम को डिजाइन करने, मूल्यांकन करने और व्याख्या करने में सक्षम बनाया जा सके और इसके साथ ही इंटरडिसिप्लिनरी समस्या-समाधान, नैतिक जागरूकता और अनुवाद संबंधी प्रभाव को बढ़ावा दिया जा सके।

एनपीजी ने सड़क,परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 7 परियोजनाओं की समीक्षा की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 108वीं बैठक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में आयोजित की गई। इस बैठक में एनपीजी ने सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 7 परियोजनाओं की समीक्षा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि डीपीआईआईटी में एनपीजी की 108वीं बैठक आयोजित की गई। जिसका उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करना था। बैठक में विशेष रूप से प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) के अनुरूप बहुआयामी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार पर जोर दिया गया। मंत्रालय के मुताबिक एनपीजी ने बैठक में एकीकृत बहुआयामी अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों तक अंतिम-मील कनेक्टिविटी और 'संपूर्ण सरकारी' दृष्टिकोण के प्रधानमंत्री गतिशक्ति सिद्धांतों के

अनुरूप 7 सड़क परियोजनाओं का गहन विश्लेषण किया। एनपीजी की इन पहलों से लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि, यात्रा समय में कमी और परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन हुआः सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच):- तमिलनाडु में सलेम-कुमारपालयम खंड पर एनएच-544 के छह लेन का निर्माण- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तमिलनाडु के सलेम-कुमारपालयम खंड पर एनएच-544 के छह लेन वाली सड़क निर्माण परियोजना का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना के तहत सलेम से कुमारपालयम तक 102.035 किलोमीटर लंबा छह लेन वाला कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो कोच्चि-कोयंबटूर-बेंगलुरु के अत्यधिक व्यस्त मार्ग पर स्थित है।

अमरावती आउटर रिंग रोड का निर्माण (आंध्र प्रदेश):- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में 189.93 किलोमीटर लंबी अमरावती आउटर रिंग रोड (ओआरआर) विकसित करने की योजना बनाई है। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करना और विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली समेत अमरावती राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क को सशक्त बनाना है।

जम्मू-कश्मीर में रफीबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार तक पक्की शोल्डर वाली दो लेन सड़क का निर्माण (चौड़ीकरण/मजबूतीकरण) :- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में रफीबाद से कुपवाड़ा व चौकीबल होते हुए तंगधार तक पक्की शोल्डर के साथ 62.10 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क के निर्माण (चौड़ीकरण/मजबूतीकरण) का प्रस्ताव पेश किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना है। लेह बाईपास के निर्माण के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें पक्के शोल्डर सहित दो लेन की सड़क का निर्माण, स्थानीय प्राधिकरण सहयोग और उपयोगिता स्थानांतरण जैसे पहलू शामिल हैं। यह परियोजना फ्यांग गांव के पास एचपीसीएल संयंत्र से आरंभ होकर लेह-मनाली राजमार्ग से जुड़ते हुए प्रस्तावित है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लद्दाख में फ्यांग से लेकर 48.108 किलोमीटर लंबे लेह बाईपास-1 का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है, जो एनएच-01 (श्रीनगर-लेह) को एनएच-03 (लेह-मनाली) से जोड़ने वाला एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। चित्रकूट-मझगवां-सतना खंड (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) के लिए मौजूदा दो लेन वाली विभाजित सड़क को चार लेन वाली विभाजित सड़क में बदलने का प्रस्ताव (पक्की शोल्डर सहित)- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले 77.102 किलोमीटर लंबे चित्रकूट-सतना कॉरिडोर को दो लेन की सड़क से चार लेन वाली विभाजित सड़क में बदलने का प्रस्ताव दिया है। राउरकेला से सिथियो (ओडिशा और झारखंड) तक चार लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा और झारखंड के बीच राउरकेला से सिथियो तक 156.10 किलोमीटर लंबे चार-लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह मार्ग पांच जिलों से होकर गुजरेगा और इसे प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत आर्थिक केंद्रों को प्रभावी ढंग से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर में समुद्री खाद्य क्लस्टर और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) भी शामिल हैं, जिससे क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय संपर्क को बेहतर बनाया जाएगा। कन्हौली से शेरपुर (बिहार) तक छह लेन का ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड राजमार्ग (एनएच-131जी) का निर्माण- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पटना रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत कन्हौली से शेरपुर तक 9.98 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा है जो एनएच-30 और एनएच-922 को जोड़ेगी। इससे क्षेत्रीय संपर्क को मजबूती मिलेगी और पटना व आस-पास के इलाकों में यातायात जाम में कमी आएगी।

संक्षिप्त समाचार

राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता 2025-26 के 40 विजेताओं का सम्मान, युवाओं के सपनों को मिली नई उड़ान

लोकतंत्र की शान : लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर, रोजगारोन्मुख और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) द्वारा इंडिया स्किल्स कॉम्पीटिशन 2025-26 के अंतर्गत राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं का भव्य सम्मान समारोह बुधवार को कौशल विकास मिशन मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 20 विभिन्न स्किल ट्रेड्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 40 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रत्येक स्किल ट्रेड से दो विजेताओं का सम्मान-प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस समारोह में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम एवं मिशन निदेशक पुलकित खरे ने विजेताओं को सम्मानित किया। प्रत्येक स्किल ट्रेड से दो विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कौशल, समर्पण और परिश्रम से प्रदेश का नाम रोशन किया।

युवाओं का कौशल निखारने को प्रतिबद्ध योगी सरकार-प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने विजेता प्रतिभागियों से संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभव, प्रतियोगिता यात्रा और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली तथा उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक, रोजगारोन्मुख एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे आयोजनों से युवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित होती है और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का अवसर मिलता है।

शब ए बरात पर अपनों की कब्र पर पहुंच कर की दुआ, नगर पालिका द्वारा कैंप लगाया गया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः

हसनपुरः मंगलवार को शबे बरात का त्योहार मुस्लिम समुदाय द्वारा अकीदत के साथ मनाया गया, सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगो ने अपनों की कब्र पर पहुंच कर साफ सफाई की तथा शाम को दुनिया से रुखसत कर चुके लोगों की मगफिरत का सिलसिला चालू हुआ जो बुधवार तड़के तक चला वही नगर पालिका परिषद हसनपुर द्वारा कैंप लगाकर जलपान कराया गया,बता ते चले कि मंगलवार की शाम मस्जिदों एवं कब्रिस्तानों पर रोशनी की गई कब्रिस्तानों पर पहुंचे लोगों ने मरहूम की कब्रो पर फूल चढ़ाए अगरबत्ती जलाकर खुशबू की तथा फातिहा पढ़कर उनकी मगफिरत के लिए दुआ की, ईशा की नमाज से मस्जिदों में शुरू हुआ इबादत का सिलसिला फजर की नमाज तक चला, नफिल, नमाज, कुरान की तिलावत, तस्बीह पर जिक्रे इलाही से लोगों ने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा की, सुबह फजर की नमाज तक इबादत का यह है दौर जारी रहा, पूरी रात इबादत में गुजर कर घर पहुंचे लोगों ने रोजे की नियत की, वही बच्चों ने जमकर आतिशबाजी की तथा नगर के विभिन्न कब्रिस्तानों एवं मस्जिदों पर विशेष सफाई व्यवस्था तथा रोशनी का इंतजाम किया गया साथ ही नगर के हैबतपुर बंजारा रोड स्थित शाह विलात साहब की जारत पर जलसे का आयोजन हुआ, उलमा ए किराम ने कुरान और हदीस की फजीलत बयान की, उधर नगर पालिका द्वारा जलसे के पास कैंप लगाकर लोगों को चाय का वितरण किया गया साथ ही नगर में विभिन्न स्थानों पर मस्जिदों तथा कब्रिस्तान से दुआ कर लौटने वाले लोगों को चाय आदि का वितरण किया गया, इस मौके पर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी, भाजपा नेता संजय सहदेव, सभासद मुन्ना चौहान, शाहनवाज अंसारी, मोहम्मद नौशाद अली, मोहम्मद साजिद, जाहिद अली, मुस्तकीम, इशरत उर्फ गुड्डू, लियाकत अली, दिलशाद मोनिश, मोहम्मद नाजिम, अलीमुद्दीन, जुनैद खान, मोहसिन खान, शराफत मलिक, बदर कुरैशी आदि मौजूद रहे l

लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आएं नागरिक-चेयरमैन कौसर अब्बास

सम्भल/सिरसी नगर पंचायत सिरसी के समस्त सम्मानित नागरिकों से मतदाता सूची को लेकर जागरूक होने की अपील की गई है। चेयरमैन एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कौसर अब्बास ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए अब केवल तीन दिन का समय शेष है। उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, या जिनके नाम, आयु, पता आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित समय के भीतर अपने संबंधित बूथ या निर्वाचन कार्यालय पर जाकर आवश्यक सुधार अथवा आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। चेयरमैन कौसर अब्बास ने कहा कि "आपका वोट आपकी ताक़त है" और लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। समय रहते मतदाता सूची को सही कराना हर पात्र नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। नगर पंचायत प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें, ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

लोनी विधायक के आने पर हुआ छेड़खानी के 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कोतवाली पहुंचने के बाद महिलाओं से छेड़खानी करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, बता ते चले कि हसनपुर नगर की रहरा रोड पर स्थित गोकुलधाम कॉलोनी के बाहर अवैध रूप से एक खोखा रखा हुआ है, कॉलोनी निवासी कुलदीप पोसवाल का आरोप है कि खोखे पर अपराधी किस्म के लोग एकत्र होते हैं तथा 2 फरवरी को वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे इसी बीच खोखे के पास रिहान उसके दो भाइयों ने बाइक रोककर उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करते हुए वीडियो बनाने की कोशिश की, कुलदीप पोसवाल ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी जिसको लेकर कुलदीप पोसवाल दो फरवरी की शाम को भी कोतवाली आए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें टलका दिया वही 3 तारीख को भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई तथा 4 फरवरी को लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कॉलोनी वासियों के साथ कोतवाली में पहुंचकर पुलिस पर आरोपियों से हम साज होने का आरोप लगाते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई, विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फोन पर अमरोहा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की बात रखी एवं पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की भी बात कही, तब जाकर पुलिस ने महिलाओं से छेड़खानी करने वाले चार आरोपियों जिसमें रिहान पुत्र जहीर, हारून पुत्र जहूर तथा रिहान के दो भाईयो पर मुकदमा दर्ज किया गया है, इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि हसनपुर पुलिस में तैनात दो सिपाही लगातार आरोपियों के संपर्क में है और कोतवाली में उनकी आओ भगत की जा रही है वहीं उन्होंने बताया कि कोतवाल द्वारा बताया गया है कि महिलाओं से छेड़खानी नहीं हुई है जिसको लेकर कॉलोनी वीडियो में भारी रोष है उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा की गई इस हरकत पर ऐसी मानसिकता वाले आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए इस मौके पर कॉलोनी निवासी पप्पू त्यागी, हरीश त्यागी, प्रदीप कुमार, वीरेंद्र कुमार, सुधीर कुमार, भजनलाल, अजय पाल, गौरव नागर, विवेक शर्मा, सुधीर कुमार, रवि कुमार तथा दर्जनों महिलाओं सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे l

सेना में नौकरी के नाम पर 15.67की ठगी, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज़ व नकली मोहर के प्रयोग से 15.67 लाख की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के आदेश से थाना हसनपुर में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है।थाना हसनपुर क्षेत्र की रहने वाली मनवती देवी पत्नी बलवीर ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2024 में उनके परिचित के माध्यम से सुनील कुमार, अनूप और लखीराम उर्फ लक्की ने उनके दो पुत्रों को भारतीय सेना में माली पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। अभियुक्तों ने स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती पक्की कराने की बात कहकर अलग-अलग समय पर नकद व बैंक ट्रांसफर के माध्यम से कुल 15.67 लाख की राशि प्राप्त की। आरोप है कि अभियुक्तों ने सेना के नाम के कूटरचित अपॉइंटमेंट लेटर, फर्जी लेटरहेड व नकली सील तैयार कर पीड़ित परिवार से अलग-अलग समय पर नकद व बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि प्राप्त की। बाद में दस्तावेज़ों के फर्जी होने की पुष्टि हुई। वही इस संबंध में कोतवाल प्रेमपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी लखीराम, सुनील कुमार और अनूप के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं l

सीएम योगी से मिले भाकियू प्रवक्ता, जताया आभार

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। द गंगा सहकारी चीनी मिल मोरना (मुजफ्फरनगर) के आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण के लिए 261.91 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मलिक ने कहा कि यह निर्णय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि द गंगा सहकारी चीनी मिल के आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार के लिए आपकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) एवं क्षेत्र के लाखों गन्ना किसानों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस मिल की पेराई क्षमता को प्रथम चरण में 2500 TCD से बढ़ाकर 3500 TCD तथा भविष्य में 5000 TCD तक ले जाने की योजना और इसके लिए लगभग 262 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति देना स्पष्ट करता है कि आपकी सरकार किसानों की आय, समयबद्ध गन्ना भुगतान और आधुनिक कृषि आधारित उद्योगों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। यह निर्णय न केवल मोरना क्षेत्र, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इससे पेराई में तेजी आएगी, किसानों को समय पर भुगतान होगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम न केवल इस मिल की उत्पादन क्षमता, दक्षता और तकनीकी स्तर को आधुनिक बनाएगा, बल्कि क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों की आय, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा।

लंबित आवास मामलों के निस्तारण हेतु 'एकमुश्त समाधान योजना' लागू करें: मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

लखनऊ :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई 'एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)' लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जिसमें समाधान तेज, पारदर्शी और सभी के लिए व्यावहारिक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की किसी भी योजना में लंबित भुगतान या विवादित आवंटन राज्य की विकास गति को धीमा करते हैं। इसलिए आवास विभाग को ऐसी समाधान-प्रधान व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो और आवंटियों को भी राहत मिले। उन्होंने कहा कि यह योजना जन-केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें हर वास्तविक आवंटी को स्पष्ट और सरल विकल्प उपलब्ध हों। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस-2020 योजना से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ था, लेकिन कोविड-19 के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर पाए। विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में प्रदेश के विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में मौजूद ऐसे सभी डिफॉल्ट मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओटीएस-2026 योजना को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी स्वरूप दिया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, किस्तों में भुगतान की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय यह ध्यान रहे कि योजना के मूल में आम आदमी को राहत देने का ही भाव निहित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग द्वारा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को राजस्व भी प्राप्त होगा।

सीएम योगी का बाल प्रेम : जनसेवा, संवेदना और सुशासन की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची मासूम बच्ची की जिद हो या चॉकलेट की मांग करने वाले बच्चों की हठ। जिन मुख्यमंत्री का नाम सुनकर अपराधी कांप उठते हैं, बच्चे उन्हीं से मिलकर सहजता से अपनी जिद मनवा लेते हैं। कहते हैं, 'बच्चे मन के सच्चे', वे अपने दिल की भावना को अत्यंत निश्छलता से प्रकट कर देते हैं, यही भाव उस समय सामने आया, जब सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते ही एक छोटी बच्ची ने उन्हें सैल्यूट किया। सीएम ने भी मुस्कुराते हुए बच्ची को खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए कहा। उनका यह बाल प्रेम उनके कोमल हृदय व सर्वसुलभ होने के साथ-साथ जनसेवा, संवेदना व सुशासन की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री के बच्चों से जुड़ाव और उनके साथ भावनात्मक संवाद के कई दृश्य समय-समय पर सामने आते रहते हैं। विगत सोमवार को 'जनता दर्शन' में मां के साथ आई बच्ची अनाबी अली से सीएम का संवाद इन दिनों चर्चा में है। अपने एडमिशन के लिए जिद, फिर एबीसीडी व कविता सुनाकर अनाबी ने सीएम का दिल जीत लिया। वहीं मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मंदिर में एक बच्चे से "और क्या चाहिए" पूछना और उसका मासूम जवाब सुनकर खिलखिलाकर हंसना भी उनके बालप्रेम को प्रकट करता है। बच्चों से अत्यंत आत्मीयता से संवाद और उनके भविष्य को लेकर त्वरित निर्णय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। बीते दिनों 'जनता दर्शन' में दो साल की अनन्या से संवाद भी लोगों के मन को छू गया। इसी तरह 31 दिसंबर को मेजर की बेटी अंजना भट्ट ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने मकान पर कब्जे की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर न सिर्फ मकान को कब्जा मुक्त कराया, बल्कि आरोपियों पर एफआईआर व तत्काल गिरफ्तारी भी कराई। यह मामला सीएम की जन समस्याओं के प्रति गंभीरता को प्रकट करते हुए स्पष्ट संदेश देता है कि वे कानून व्यवस्था, बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों का समाधान कराने में तनिक भी विलंब नहीं करते। कानपुर की मूक-बधिर युवती खुशी गुप्ता की कहानी भी इन दिनों हर किसी की जुबां पर है। मुख्यमंत्री से मिलने की उसकी जिद और अकेले पैदल चलकर लखनऊ पहुंचने की जानकारी जब सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली तो उन्होंने उसे बुलाकर उसके बनाए चित्रों को स्वीकार किया और उसके शिक्षित-सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के अपनत्व से भाव-विभोर खुशी की 'अनकही भावनाओं' ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों के बीच मुख्यमंत्री की 'प्रदेश ही परिवार' धारणा की विश्वसनीय तस्वीर पेश की। 'जनता दर्शन' के जरिए लखनऊ की अनाबी अली, कानपुर की मायरा, गोरखपुर की पंखुड़ी और मुरादाबाद की वाची का स्कूल में एडमिशन कराना भी सीएम योगी की संवेदनशीलता का हिस्सा है। कानपुर की नन्ही मायरा ने कहा था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं। इस पर सीएम ने तत्काल उसका प्रवेश कराने का निर्देश दिया। वाची ने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, सीएम ने उसका भी प्रवेश कराया। गोरखपुर की पंखुड़ी की फीस माफ कराने के साथ ही उसे पुनः विद्यालय भेजना भी सुनिश्चित कराया।

शबे बरात पर नन्हे अजलान ने की अल्लाह से दुआ

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

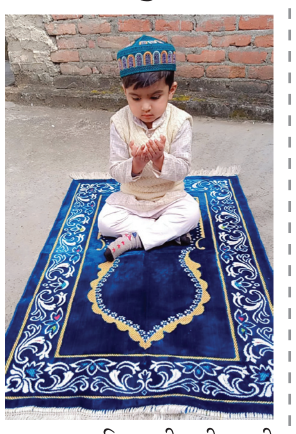

हसनपुरः मंगलवार को शबे बरात पर जहां बड़ो ने कब्रिस्तानो पर पहुंचकर दुनिया से रुखसत कह चुके लोगों की मगफिरत की दुआ की गई वही छोटे बच्चे भी इस मुक़द्दस रात को लेकर उत्साहित दिखे, बताते चले कि नगर के मोहल्ला लालबाग बजरिया निवासी 3 वर्षीय मोहम्मद अजलान पुत्र शोएब ने चार दिवारी में ही फर्श पर बैठकर अल्लाह से दुआ मांगी, मोहम्मद अजलान द्वारा इस तरह हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते देखा सभी ने अजलान की तारीफ की तथा अजलान के उज्वल भविष्य की कामना की, बता ते चले कि नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अपने बड़े परिजनों के साथ कब्रिस्तानो पर पहुंच कर भी दुआ की गई वहीं बच्चों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी की, वही नगर में मुस्लिम क्षेत्र में नगर की मुस्लिम कमेटियों द्वारा तथा समाजसेवियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर खाद्य सामग्री का वितरण किया गया जिसमें चाय, फल आदि प्रमुख रूप से रहे, वही सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाल प्रेमपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ रातभर गस्त पर रहे l

सरकार की विकास नीति को ज़मीन पर उतारते दिखे चेयरमैन कौसर अब्बास, वार्ड नं0 4 में पथप्रकाश व सुविधाओं का किया सघन निरीक्षण

लोक तंत्र की शान

सम्भल/सिरसी नगर पंचायत सिरसी के चेयरमैन कौसर अब्बास ने सरकार की विकासपरक नीतियों को धरातल पर उतारने की दिशा में वार्ड नं० 4 में पथप्रकाश (स्ट्रीट लाइट) सहित अन्य नागरिक सुविधाओं का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया। चेयरमैन कौसर अब्बास ने साफ शब्दों में कहा कि विकास सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि गलियों और सड़कों पर दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए और जनता को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर न किया जाए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई तय है।<चेयरमैन ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर वार्ड में समान रूप से विकास पहुंचे और नगर पंचायत सिरसी उसी सोच के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीति का मतलब जनता की सेवा है, न कि सिर्फ बयानबाज़ी। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने चेयरमैन के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। चेयरमैन की सक्रियता से वार्डवासियों में यह संदेश गया कि नगर पंचायत अब सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, बल्कि उन्हें ज़मीनी हकीकत में बदल भी रही है।

कैंसर इलाज के लिए अब दिल्ली-मुंबई पर आश्रित नहीं यूपी

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। कैंसर के इलाज के लिए अब उत्तर प्रदेश के मरीजों को दिल्ली या मुंबई की ओर रुख करने की मजबूरी नहीं रही। लखनऊ से वाराणसी तक स्थापित कैंसर ट्रीटमेंट नेटवर्क प्रदेश को देश में सबसे बड़ी व सुलभ कैंसर उपचार व्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। लखनऊ में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान और वाराणसी में टाटा मेमोरियल की तर्ज पर बने केंद्रों की सफलता ने यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी है। स्थिति ये है कि अब बिहार व नेपाल तक के मरीज इलाज के लिए यूपी आ रहे हैं। योगी सरकार के बहुस्तरीय प्रयासों का परिणाम है कि कैंसर की स्क्रीनिंग से लेकर सुपर स्पेशियलिटी इलाज और आर्थिक सहायता तक, हर स्तर पर सुविधाएं मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत स्वास्थ्य ढांचे का व्यापक विस्तार किया गया है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में 220 बेड, एक छत के नीचे समग्र इलाज लखनऊ के चक गजरिया में स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान आज अत्याधुनिक कैंसर उपचार का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। 220 बेड, आधुनिक रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी की सुविधाओं के साथ यह संस्थान एक ही छत के नीचे समग्र इलाज उपलब्ध करा रहा है।

वाराणसी में त्वरित और प्रभावी इलाज-वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल पूर्वांचल के लिए जीवनरेखा साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों से शुरू हुए ये संस्थान टाटा मेमोरियल मॉडल पर कार्य कर रहे हैं। लखनऊ और वाराणसी के बीच विकसित यह सुविधा रेफरल सिस्टम, विशेषज्ञ परामर्श और तकनीकी सहयोग के जरिए मरीजों को त्वरित और प्रभावी इलाज दे रही है।

स्क्रीनिंग से लेकर सर्जरी तक मजबूत व्यवस्था-पिछले तीन वर्षों में सरकारी अस्पतालों में कैंसर ओपीडी, सफल सर्जरी और उपचार में बड़ी सफलता मिली है। जिला गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लिनिक के माध्यम से कैंसर की शुरुआती जांच सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विशेष रूप से महिलाओं में स्तन व सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बीमारी का पता शुरुआती चरण में ही चल सके और मृत्यु दर घटाई जा सके।

संक्षिप्त समाचार

पटना जू में मादा जिराफ 'शांति' की मौत, 21 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

लोकतंत्र की शान : पटना। पटना जू में मादा जिराफ 'शांति' की मंगलवार रात को उम्र 21 साल की उम्र में मौत हो गयी है। पटना जू प्रशासन द्वारा मौत का प्रारंभिक कारण प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बताया गया है। शांति के मौत के कारणों के डिटेल जांच के लिए सैम्पल को विशेषज्ञ संस्थानों में भेजा जा रहा है। फिलहाल शांति के दो बच्चे "अमन और नंदनी" पटना जू में है। पटना जू और देश के चिड़ियाघरों में जिराफों के संरक्षण प्रजनन में मादा जिराफ "शांति" का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

USA से लाया गया था मादा जिराफः शांति का जन्म दिनांक 20 जुलाई 2005 को यू.एस.ए के सेन डियागो जू में हुआ था। वर्ष 2006 में मादा जिराफ को सेन डियागो जू से संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में वन्यजीव अदला-बदली कार्यक्रम के तहत लाया गया था। मादा जिराफ "शांति" के द्वारा 2011 में पटना जू में पहला बच्चा

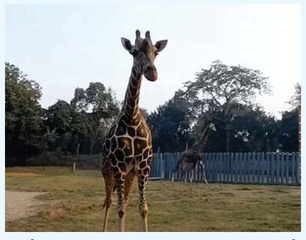

"नव्या" को जन्म दिया गया। 2011 से वर्ष 2023 तक मादा जिराफ के द्वारा 6 बच्चों को जन्म दिया गया है। मादा जिराफ के बच्चों को देश के अन्य चिड़ियाघरों- नंदनकानन जू, भुवनेश्वर, गुवाहटी जू, असम, मैसूर जू, कर्नाटक को दिया गया है। पटना जू में ठंड के मौसम को देखते हुए वन्यजीवों के बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए। इसमें से जिराफ के लिए भी खास इंतजाम थे। जिराफ के लिए खुले मैदान में पुआल बिछाया गया, ताकि वह ठंड में उसपर बैठ सके। इसके साथ ही छोटे शावक को केयर टेकर द्वारा बोरे का खोल बनाकर पहनाया गया है। तीन बार में खाना दिया जा रहा। पीने और नहाने के लिए जू-प्रबंधन की ओर से गर्म पानी का खास तौर पर इंतजाम किया गया। उन्हें हल्का गर्म पानी पीने के लिए दिया जाता। इसके साथ ही उस पानी में नमक मिलाया जा रहा।

रेंट एग्रीमेंट के विवाद को लेकर फायरिंग, 50 लाख की रंगदारी मांगने का भी आरोप, 2 बार किया टारगेट

लोकतंत्र की शान : पटना। पटना में दीघा इलाके के लोयला स्कूल के पास शंभू सिंह नाम के शख्स पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हालांकि शंभू सिंह फायरिंग करने वाले बदमाश से भीड़ गए। हाथ पकड़कर ऊपर कर दिया। जिससे हवाई फायरिंग हो गई। वहां मौजूद लोगों ने इसी बीच उस शख्स को पकड़ लिया। बुरी तरह से मारने पीटने लगे। पीड़ित पक्ष ने पीटने के बाद पुलिस को खबर की। मौके पर पुलिस आई और आरोपी को लेकर थाने चली आई। गंभीर चोट होने के चलते पुलिस ने आरोपी का इलाज भी कराया। इधर, दो अन्य आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा कि 50 लाख की रंगदारी भी मांगी गई थी। वहीं, पीड़ित पर दोबारा हमला किया गया है। रेंट के पैसे को लेकर विवाद था। प्रभारी सेंट्रल एसपी भानु प्रताप ने बताया कि आरोपी की पहचान बिहटा के रहने वाले सिकंदर उर्फ राहुल के तौर पर हुई

है। पूर्व से ही दोनों के बीच रेंट के रुपए को लेकर विवाद चल रहा है। आरोपी का कहना है कि शंभू सिंह के यहां रुपए बकाया है। वहीं, शंभू सिंह का कहना है कि कोई रुपए बकाया नहीं है। इसी बात के विवाद में सिकंदर ने शंभू को टारगेट कर के फायरिंग की थी। आरोपी के पास से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा मिले हैं। फिलहाल और भी पूछताछ की जा रही है। एक के खिलाफ दिया आवेदन इधर, पीड़ित शंभू सिंह ने दीघा थाने में सिकंदर उर्फ राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आस पास में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही है। घटनास्थल से एक बाइक भी बरामद की गई थी। जिसके नंबर प्लेट पर टेप चिपकाया गया था। पुलिस को आशंका है कि इसी बाइक से अपराधी घटना को अंजाम देने आए थे।

बस से 4 लाख की शराब जब्त, दनियावां में ड्राइवर-खलासी गिरफ्तार, रांची से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी खेप

लोकतंत्र की शान : पटना। पटना के दनियावां थाना क्षेत्र में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की एक बस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में बस के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये है। बस से कुल 282 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए ड्राइवर की पहचान वैशाली निवासी धर्मजीत और खलासी की पहचान मोतिहारी निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारी हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी रांची से विदेशी शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहे थे। शराब को सरकारी बस के जरिए ले जाया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। वे पटना के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर दनियावां

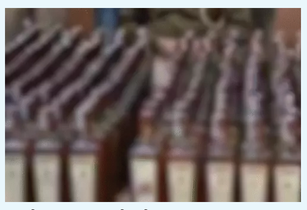

थाने की पुलिस ने होरिल बीघा गांव के पास उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया। दनियावां थाना प्रभारी ने बताया कि, हमें गुप्त सूचना मिली थी कि BSRTC की एक बस से शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होरिल बीघा गांव के पास चेकिंग अभियान चलाया। जैसे ही संदिग्ध बस वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान बस से 282 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसके बाद ड्राइवर और खलासी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया।' पुलिस अब यह जांच कर रही है कि शराब की सप्लाई किसके कहने पर की जा रही थी, इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और क्या इस मामले में परिवहन निगम के अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं? दनियावां थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

वैशाली में अफीम-हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई, हुंडई वेन्यू से बरामदगी, झारखंड के तीन तस्कर गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली पुलिस ने एक विशेष अभियान में 1 किलो 4 ग्राम अफीम और 158 ग्राम हेरोइन जब्त की है। ये मादक पदार्थ सराय टोल प्लाजा के पास एक हुंडई वेन्यू कार से बरामद किए गए। इस संबंध में झारखंड के तीन तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वैशाली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, 3 फरवरी 2026 को जिला आसूचना इकाई (DIU) वैशाली को सूचना मिली कि नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से मुजफ्फरपुर-सराय होते हुए झारखंड जाने वाली एक सफेद हुंडई वेन्यू कार में मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक ने जिला आसूचना इकाई वैशाली और सराय थाना पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया। इस टीम ने 3 फरवरी 2026 को शाम लगभग 7:30 बजे सराय टोल टैक्स के पास संदिग्ध हुंडई कार को रोका। कार में चालक सहित कुल तीन लोग सवार थे। पूछताछ में चालक की पहचान चतरा निवासी ललन कुमार के तौर पर हुई। पिछली सीट पर बैठे दो अन्य व्यक्तियों की पहचान पलामू निवासी श्रवण कुमार और चतरा निवासी अनिल कुमार के रूप में की गई। ये सभी झारखंड राज्य के निवासी हैं। एक दंडाधिकारी की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ तीनों व्यक्तियों और कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, कार के गियर बॉक्स के बाईं ओर यात्री सीट के बगल से एक काले रंग की पॉलिथीन में अफीम मिली। इसके अतिरिक्त, गियर के पीछे बने बॉक्स से एक सफेद प्लास्टिक के डिब्बे में ब्राउन कलर का पाउडर (हेरोइन) बरामद हुआ। मौके पर ही दोनों मादक पदार्थों का वजन किया गया, जिसमें अफीम का वजन 1 किलो 4 ग्राम और हेरोइन का वजन 158 ग्राम पाया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों और कार मालिक के खिलाफ सराय थाना कांड संख्या 29/26 दर्ज किया गया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

नितिन नवीन के पटना दौरे को लेकर भाजपा की बैठक

लोकतंत्र की शान , पटना

❒ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे बिहार, बापू सभागार में होगा नागरिक अभिनंदन

भारतीय जनता पार्टी के नव-नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 और 10 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला बिहार आगमन होगा। उनके आगमन को लेकर बिहार भाजपा में खासा उत्साह है और पार्टी स्तर पर भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में स्वागत कार्यक्रम, संगठनात्मक बैठकों और दौरे के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बिहार की मिट्टी के लाल हैं नितिन नवीन- संजय सरावगीः बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि, 'बिहार की मिट्टी के लाल और हमारे अपने नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला आगमन 9 और 10 फरवरी को अपने ही प्रदेश बिहार में हो रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है।'

9 फरवरी को बापू सभागार में भव्य नागरिक अभिनंदनः प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि, '9 फरवरी को पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल होंगे। इस दौरान नागरिक अभिनंदन समारोह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे।'

नितिन नवीन के दौरे के दौरान भाजपा विधानमंडल दल की भी बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी राजनीतिक रणनीति और प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संजय सरावगी ने बताया कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार आए थे, तब भाजपा की ओर से मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में उनका भव्य अभिनंदन किया गया था। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका अभिनंदन बापू सभागार में किया जाएगा, जिसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है।

10 फरवरी को विधानसभा जाएंगे नितिन नवीनः संजय सरावगी ने बताया कि, 'राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक भी हैं, ऐसे में 10 फरवरी को वे विधायक के नाते बिहार विधानसभा जाएंगे। इस दिन भी उनका कार्यक्रम लगातार और व्यस्त रहेगा। नितिन नवीन ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आवास पर जाने की इच्छा भी व्यक्त की है, जिस पर पार्टी स्तर पर कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसके बाद वे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।' प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि, 'दोनों ही दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम लगातार रहेगा और उनके स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।' भाजपा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले बिहार आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मधुबनी समेत 10 जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 100 मीटर

लोकतंत्र की शान , पटना

♦ पटना से जाने वाली 6 ट्रेनें लेट, पछुआ हवाओं ने फिर बढ़ाई ठिठुरन

बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मधुबनी, बगहा, बेतिया, गोपालगंज समेत 10 जिलों में घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 100 के करीब है। लोगों को गाड़ियों की लाइट चालू कर के चलना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से पटना से जाने वाली 6 ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कटिहार समेत 25 जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 100 मीटर के आसपास विबिजिलिटी रहने की संभावना है। सुबह और देर रात घनी धुंध छाई रहेगी। साथ ही लोगों को कनकनी ज्यादा महसूस हो सकती है। बीते 24 घंटे में 3 जिलों में कोहरा दिखाई दिया। इन जिलों में विजिबिलिटी लगभग 100 मीटर के आसपास रही। वहीं, 8°C न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर सबसे ठंडा जिला रहा।

पटना में पछुआ हवाओं से सुबह-सुबह ठिठुरन महसूस हो रही है। मधुबनी में पछुआ हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। विजिबिलिटी 100 की करीब है। जमुई और नालंदा में मौसम साफ है। सुबह-सुबह धूप निकली है। कोहरे की वजह से पटना से जाने वाली 6 ट्रेनें लेट चल रही हैं।

कई जिले में 2 दिनों से क्यों छा रहा घना कोहराः पिछले 2 दिनों से राज्य के कई जिलों में लगातार घना कोहरा दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका मेन कारण उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर प्रभाव और वातावरण में नमी का बढ़ना है।

रात में हवा की रफ्तार काफी कम हो जा रही है, जिससे नमी जमीन के पास ही जमा हो रही है। साथ ही न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होने के कारण कोहरे की स्थिति और मजबूत हो गई है। साफ आसमान और शांत मौसम की वजह से सुबह के समय कोहरा देर तक छाया रह रहा है।

नाबालिगों से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व 25हजार के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला

विशेष न्याायलय पॉक्सो एक्ट, सीधी ने सुनाया फैसला

लोकतंत्र की शान

सीधी। दादी के घर से अपने घर लौट रही पांच साल के अबोध बालिका को उठाकर जंगल मे ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी का आरोप प्रमाणित होने पर पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कठोर कारावास एवं 25हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय के अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी ने बताया कि अभियोक्त्री की मां के द्वारा इस आशय की देहाती नालशी अस्पताल चौकी सीधी में लेख करायी कि दिनांक 09.05.2023 को शाम करीबन 07:00 बजे वह घर के अंदर खाना बना रही थी। उसकी लड़की अभियोक्त्री उम्र लगभग 05 वर्ष पड़ोस में ही अपनी दादी के घर चली गई थी, जब काफी देर तक नहीं लौटी तो वह और उसके घर वाले उसे आस-पास टार्च लेकर ढूंढने लगे। ढूंढते हुए पास के जंगल में गये तो देखा कि उसके पड़ोस का केमलभान बैगा उसकी बच्ची को छोड़कर भाग रहा है। तब वह और उसके साथ के लोग दौड़कर बच्ची के पास गये और बच्ची से पूछा तो उसकी बच्ची ने बताया कि जब वह दादी के यहां से घर लौट रही थी तब केमलभान उसे गोद में उठाकर ले गया और जंगल में पत्थर में पटककर उसकी चड्डी उतार दिया था और अपनी छुन्नी (लिंग) उसके पेशाब के रास्ते में डाला था और उसका गला दबा रहा था, चिल्लाने नहीं दे रहा था। पटकने से उसकी लड़की की पीठ में खरोंचदार चोट आयी है और उसके पेशाब वाले रास्ते में खून निकल रहा था। उस समय लगभग रात्रि के लगभग 12-01 बज गये थे। केमलभान मौके से फरार हो गया था। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया था लेकिन वह मौके से भाग गया। फरियादी ने अभियोक्त्री को लेकर पुलिस चौकी खड्डी गयी थी तथा अभियोक्त्री का स्वास्थ्य ठीक न होने से उसे जिला अस्पताल सीधी लाया गया। उक्त पर से अस्पताल चौकी सीधी में जीरो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 0/2023 अंतर्गत धारा 363, 366, 376(ए)(बी) भा.दं.सं. एवं धारा 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दर्ज की गई तथा पश्चात् में थाना रामपुर नैकिन को उक्त बिना नंबरी नालशी प्राप्त होने पर थाना रामपुरनैकिन द्वारा असल अपराध क्र. 416/2023 में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। मामले की विवेचना निरी. सुधांशू तिवारी के द्वारा की गई है। मामले की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक एससी/12//2023 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशान्त कुमार पाण्डेय के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त केमलभान बैगा पिता रामलखन बैगा, उम्र 35 वर्ष, निवासी अंतर्गत थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र. को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा एवं 20,000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि रू. 25,000/- अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में क्षतिपूर्ति स्वरूप अभियोक्त्री को दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया। प्रकरण में न्यायालयीन संमंस/वारण्ट कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जारी किये गये।

पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की मांग राज्यसभा में उठी

लोकतंत्र की शान , पटना

हरिवंश, उपसभापति, राज्यसभा

♦ उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में रखी मांग कहा- पाटलिपुत्र नाम गौरव का प्रतीक

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाह ने पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की मांग उठाई। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बातें रखी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा,'महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अतीत के क्षणों को याद करते हुए कहा कि जब देशवासी अतीत के महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणा विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को गति देती है। महामहिम के इन पंक्तियों से हमें भारत का वह कालखंड याद आता है, जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था।' उन्होंने कहा, 'मौर्य काल के वक्त हमारे देश की सीमा बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल सब भारत की सीमा में हुआ करता था। इसके प्रतीक चिन्ह आज भी अतीत के रूप में हमारे सामने हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन कालखंडों पर जो धूल पड़ा है, उसको साफ करें और जीवंत बनाने का काम करें।'

मौर्य साम्राज्य के गौरव की दिलाई यादः इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 'मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं, जिसे सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। बिहार जब मौर्य का शासन था, उस समय बिहार का गौरव और सम्मान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। मौर्य काल के समय में बिहार का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। इनके चिन्ह हर जगह मशहूर हैं।

बंबई का नाम मुंबई हुआ तो अब पटना का नाम पाटलिपुत्र हो- उपेंद्र कुशवाहाः उपेंद्र कुशवाहा ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि, 'इससे पहले कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया। ठीक उसी तरह उड़ीसा का ओडिशा और बंबई का नाम बदलकर मुंबई रखा गया। जब सब शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, फिर पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों नहीं किया जा सकता है।

रिटायर्ड महिला टीचर मौत केस हो सकती है खुदकुशी, पुलिस कर रही जांच

लोकतंत्र की शान , पटना

❒ फिंगरप्रिंट्स से खुल सकता मामला, गले-हाथ पर हल्के कट के थे निशान

पटना के शास्त्री नगर इलाके के AG कॉलोनी पार्क से सटे एक मकान में 17 जनवरी 2026 को रिटायर्ड महिला टीचर माधवी कुमारी (78) की संदिग्ध परिस्थिति में बॉडी मिली थी। गर्दन पर धारदार हथियार से कटने के निशान पाए गए थे। इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। हालांकि अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना के वक्त पुलिस ने बेड के पास से एक ब्लेड बरामद किया था। इस ब्लेड को FSL जांच में भेजा गया है। ब्लेड पर किसके फिंगरप्रिंट हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पुलिस सूत्रों की मानें तो फिलहाल पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों एंगल से इस मामले की जांच कर रही है।

पति की 2023 में हुई थी मौतः मृतक महिला धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। घटना से पहले उसी घर में पूजा पाठ भी कराई थीं। महिला की एक बेटी और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा उज्ज्वल देहरादून में प्रोफेसर है। दूसरा बेटा उत्कल कुमार दिल्ली में मल्टीनेशनल बैंक ऑफ अमेरिका में अधिकारी है। पति अमरेंद्र कुमार दास AG ऑफिस में अधिकारी थे और 2008 में रिटायर्ड हुए थे। उनकी मौत 2023 में हुई थी। सुसाइड की ओर इशारा

लॉ एंड ऑर्डर सचिवालय SDPO 2 साकेत कुमार ने बताया कि FSL रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे। सीसीटीवी कैमरे में कोई भी स्पेक्ट नहीं दिखा है। कमरे के अंदर जबरन घुसने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मृतक महिला की हैंडराइटिंग FSL को फिंगरप्रिंट के लिए भेजी गई है। गले पर भी डीप कट के निशान नहीं थे। इसके अलावा दोनों हाथ के नस भी हल्के-हल्के कटे थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी सुसाइड की ओर इशारे कर रहे हैं। परिजनों ने भी किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है।

जदयू में शामिल रियाजुल हक बोले-राजद पूंजीपतियों की पार्टी बनी

लोकतंत्र की शान , पटना

♦ कहा- नीतीश कुमार के काम का समर्थक रहा हूं, विधायक अमरेंद्र पांडे बोले- वो जमीनी स्तर के नेता

जेडीयू कार्यालय में बुधवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रेयाजुल हक राजू अपने समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे मौजूद रहे। सभी नेताओं ने रियाजुल और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया। मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू लगातार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। रेयाजुल हक राजू के आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बिहार के विकास के एजेंडे को और तेज करेगी।

अमरेंद्र पांडे बोले- रियाजुल जमीनी स्तर पर काम करतेः इस मौके पर जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे ने भी रियाजुल हक राजू के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया और कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं के आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग जेडीयू से जुड़ रहे हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद रेयाजुल हक राजू ने कहा कि वे भले ही पहले किसी अन्य दल में रहे हों, लेकिन मन से हमेशा नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है, वह किसी से छिपा नहीं है और वे लंबे समय से उनके कार्यों के प्रशंसक रहे हैं।

रेयाजुल बोले- राजद अब पूंजीपतियों की पार्टी बन चुकी हैः रेयाजुल हक राजू ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद अब पूंजीपतियों की पार्टी बन चुकी है, इसी वजह से उन्होंने उस पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय के साथ विकास की राजनीति करती है। रियाजुल हक ने मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील की कि वे राजद छोड़कर जेडीयू से जुड़ें और नीतीश कुमार के विकास मॉडल को मजबूत करें।

रेयाजुल हक उर्फ राजू लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से जुड़े रहे और 2025 में विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हुए। राजू गोपालगंज जिले की बरौली विधानसभा सीट से सक्रिय रहे हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से महागठबंधन के वोट समीकरण पर असर की चर्चा हुई। महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में उन्हें बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान वे अल्पसंख्यक मुद्दों पर सरकार और प्रशासन के साथ संवाद का चेहरा रहे। उनके कार्यकाल में कोई बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने सवाल जरूर उठाए।

छः माह से नहीं मिला वेतन दाने दाने को मुहताज आदिवासी विकास विभाग का कर्मचारी

लोकतंत्र की शान

सीधी । आदिवासी विकास सीधी के भृत्य रामलाल केवट को 6 माह से वेतन भुगतान न होने से परिवार के भरण-पोषण को लेकर परेशान है। सहायक आयुक्त जोधा सिंह को आवेदन देकर फरियाद करने के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। भृत्य रामलाल केवट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक डब्लू.पी 31788 / 2025 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2025 में, माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता को उनके अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर निराकरण करें तथा तब तक याचिकाकर्ता को शा.उ.मा.वि. कमछ जिला सीधी में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। दरअसल याचिकाकर्ता को कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 3087 / स्था. सामान्य / आदि.वि. / 2015 दिनांक 06.07.2015 द्वारा निलम्बन से विभागीय जांच उपरान्त बहाल किया जाकर हाई स्कूल भदौरा (रुँदा) विकासखण्ड कुसमी जिला सीधी में पदस्थ किया गया था। कार्यालयीन आदेश कमांक 1793/स्था. सामान्य/आंदि. वि./2020 दिनॉक 31.03.2020 द्वारा निलम्बन अवधि को कार्यकाल मानते हुए स्वत्वों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4866 / स्था. सामान्य / जन. जा का./2019 दिनाँक 29.08.2019 द्वारा त्वारित व्यवस्था अन्तर्गत शासकीय माध्यमिक शाला कमछ में कार्य करने हेतु आदेशित किया तथा वेतन मूल पदस्थ संस्था से प्राप्त होती रही। आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. के पत्र कमांक / स्था.4/टी (27) / 2024 / 23442 दिनांक 10.12.2024 द्वारा समस्त सहायक आयुक्त जिला सयोंजक म.प्र. को किये गये संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करनें के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिपालन में कार्यालयीन आदेश कमाक / 3981 / शिक्षा स्था./ज.जा.का. वि./2024 दिनांक 11.12.2024 द्वारा सीधी जिला अन्तर्गत समस्त संलग्नीकरण आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. के निर्देशानुसार समाप्त कर दिये गये थे, उसी अनुक्रम में याचिकाकर्ता को भी शा.उ.मा.वि. कमछ विकासखण्ड कुसमी जिला सीधी के पत्र कमांक 1699/स्था. शिक्षा/2025 दिनोंक 18.07.2025 द्वारा मूल पदांकित संस्था हाई स्कूल भदौरा (रुँदा) विकासखण्ड कुसमी जिला सीधी के लिये कार्यमुक्त किया गया था जिसके विरूद्ध याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक डब्लू.पी. 31788 / 2025 प्रस्तुत कर प्राचार्य कमछ द्वारा कार्यमुक्त दिनॉक 18.07.2025 में ऊपर वर्णित आदेश दिनॉक 22.08.2025 पर राहत की मांग की गई थी।माननीय न्यायालय निर्णय के अनुक्रम में रामलाल केवट, भृत्य के द्वारा कार्यालय में दिनांक 28.08.2025 को उपस्थिति दी गई। सम्बन्धीजन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनोंक 26.08.2025 का निराकरण करते हुए रामलाल केवट, भृत्य को उनकी मूल पदस्थ संस्था हाई स्कूल भदौरा (रुँदा) में होने से श्री केवट की संलग्नीकरण संस्था शा.उ.मा.वि. कमछ, से आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल के संलग्नीकरण समाप्त करनें के आदेश कमांक 23422 दिनाँक 10.12.2024 के अनुक्रम में तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा डब्लू.पी. 31778 / 2025 में पारित निर्णय के अनुक्रम में श्री केवट के अभ्यावेदन दिनॉक 26.08.2025 का निराकरण करते हुए रामलाल केवट, भृत्य को उनकी मूल पदस्थ संस्था हाई स्कूल भदौरा (रुँदा) में वापस लेने का आदेश सहायक आयुक्त सीधी द्वारा 30 जनवरी 2026 को दिया गया। इनका कहना है। भृत्य का मामला तीन दिन पहले उनके संज्ञान में आया है। शाखा प्रभारी को वेतन भुगतान को लेकर कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया जा चुका है। जोधा सिंह, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास करते हुए बोली विधायक रीती पाठक

» ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओ को दुरुस्त करने सरकार कटिबद्ध
» 250 लाख की लागत से तैयार हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसी का भवन
» क्रासर:क्षेत्र के ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

लोकतंत्र की शान रामबिहारी पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख

सीधी। विधानसभा क्षेत्र सीधी के ग्राम पंचायत सिरसी में 250 लाख रूपये की लागत से बनने वाले 06-विस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के उन्नयन एवं निर्माण कार्य का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक उपस्थित रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए आमजन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर नए अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिरसी में बनने वाला यह 06-विस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को समय पर उपचार मिलेगा और गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों तथा गंभीर मरीजों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ होगी। विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी ग्रामीण को इलाज के लिए अनावश्यक रूप से दूर शहरों का रुख न करना पड़े, बल्कि उसे अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। विधायक श्रीमती पाठक ने आगे कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और रोजगार जैसे मूलभूत क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें, स्वच्छता एवं पोषण के प्रति जागरूक रहें तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपने परिवार और समाज को स्वस्थ एवं सशक्त बनाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास एवं जनसेवा के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा और हर जरूरतमंद तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

समय सीमा में पूर्ण हो भवन निर्माण कार्य

कार्यक्रम में जनपद सदस्य दीपक पनिका, सरपंच छोटेलाल प्रजापति, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ बबिता खरे, विश्वबंधु धर द्विवेदी, पुनीत नारायण शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने की बात कही, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

चेयरमैन नरेश मलिक नलवा जी का जोरदार स्वागत किया गया

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

करनाल : केकेसी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश चेयरमैन श्री नरेश मलिक नलवा जी का केकेसी जिला कांग्रेस कमेटी करनाल द्वारा केकेसी जिला अध्यक्ष करनाल श्री बलदेव सिंह नीलोखेड़ी जी,केकेसी महिला जिलाध्यक्ष करनाल श्रीमती गुरविंदर कौर जी, केकेसी प्रदेश सिनियर डिप्टी चेयरमैन राव सुनेहर सिंह जी,केकेसी प्रदेश डिप्टी चेयरमैन श्री सरदार सरबजीत सिंह जी,केकेसी प्रदेश महासचिव श्री जोगिंदर सिंह गगसीना जी, केकेसी प्रदेश सचिव अजीत पवांर जी, केकेसी प्रदेश मिडिया सचिव श्री प्रदीप कुमार जी,एवं समस्त केकेसी टीम करनाल एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जिला करनाल में पहुंचने पर जोरदार स्वागत करने और मान सम्मान देने के लिए दिल की गहराइयों से चेयरमैन महोदय जी ने शुक्रिया अदा किया करनाल केकेसी के नवनियुक्त पदाधिकारियो को चेयरमैन महोदय जी ने नियुक्ति पत्र भी वितरित किए इस मौके पर केकेसी के प्रदेश सिनियर डिप्टी चेयरमैन श्री रामकिशन ठाकुर जी, केकेसी प्रदेश महासचिव श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, केकेसी जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र श्री सुरजीत सिंह सरपंच जी,केकेसी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश कुमार मेहरा जी,केकेसी के प्रदेश महासचिव श्री दिलबाग धिरणवास जी,केकेसी के प्रदेश महासचिव श्री सुशील धिरणवास जी,केकेसी के प्रदेश महासचिव श्री महेंद्र सिंह श्योराण जी, केकेसी फतेहाबाद जिला अध्यक्ष डॉ रामेश्वर दास कालवा जी एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा का फैसला

» क्रासर :विशेष न्याायलय पॉक्सो एक्ट, सीधी ने सुनाया फैसला

लोकतंत्र की शान

सीधी । जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने बीस साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है। बताया गया कि दिनांक 05.10.2023 को अभियोक्त्री द्वारा लिखित आवेदन पत्र थाना प्रभारी बहरी के नाम अस्पताल पुलिस चौकी सीधी में दिया गया कि दिनांक 05.10.2023 को उसके पेट में दर्द हो रहा था तब उसने अपनी मां से उक्त बात बतायी कि उसकी माहवारी अप्रैल माह से नहीं हो रही है। उसके पेट में दर्द है तब उसकी मां ने कहा कि चलो डाक्टर को दिखा देते हैं तब डाक्टर द्वारा बोला गया कि वह 07 माह की गर्भवती है। उसने अपनी मां के द्वारा पूछने पर बताया था कि होली के पहले जब वह बड़ी मम्मी के घर पूजा करने जा रही थी तो रास्ते में उसे रात करीब 07-08 बजे महुआ के पेड़ के नीचे आरोपी मुंशिया उर्फ गिरधारी कोल मिला और उससे लिपट कर उसका मुंह दबाकर उसे जमीन में पटक कर जबरदस्ती उसके गलत काम (बलात्कार) किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण अभियोक्त्री ने घटना के बारे में किसी को नहीं बतायी थी। उक्त पर से अस्पताल चौकी सीधी में जीरो पर अपराध क्र 0103/2023 अंतर्गत धारा 376, 376(3), 506 एवं धारा 5(जे)(आईआई)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दर्ज की गई। अभियोक्त्री का धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन कराया गया। पश्चात् में थाना बहरी को उक्त डायरी असल नंबर पर कायमी हेतु प्राप्त होने पर थाना बहरी द्वारा असल अपराध क्र.-518/2023 में पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक एससी/49//2023 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशान्त कुमार पाण्डेय के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त मुंसिया कोल उर्फ गिरधारी कोल पिता रामलाल कोल उर्फ बेटऊ कोल, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम नकझर खुर्द थाना बहरी, जिला सीधी म.प्र. को धारा 376(3) भादवि एवं धारा 5(जे)(आईआई)/6 पॉक्सो एक्ट में कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि रू. 10,000/- अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में क्षतिपूर्ति स्वरूप अभियोक्त्री को दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया।

खबर का असर : कुसमी—महखोर रोड से हटाई जा रही जानलेवा गिट्टी

» लोकतंत्र की शान में मध्यप्रदेश के सीधी जिले के कुसमी विकास खंड की खबर का किया था प्रकाशन

लोकतंत्र की शान, रामबिहारी पाण्डेय ब्यूरो

सीधी। कुसमी से महखोर मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत की गई लापरवाह रिपेयरिंग को लेकर खबर प्रसारित किए जाने के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया है। खबर का असर इतना स्पष्ट रहा कि खंड प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सड़क पर बिखरी खतरनाक गिट्टी हटाने का कार्य शुरू करा दिया है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों और राहगीरों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि रिपेयरिंग के नाम पर सड़क पर छोटे-छोटे गिट्टी डाल दिए गए थे, जिससे खासकर दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। मीडिया ने इस गंभीर समस्या को उठाते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों की लापरवाही और कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे। खबर सामने आने के बाद खंड प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत गिट्टी हटाने के निर्देश दिए। वर्तमान में सड़क से ढीली गिट्टी हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासनिक अमला और संबंधित विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहकर कार्य की निगरानी कर रहे हैं, ताकि आगे किसी प्रकार की लापरवाही न हो। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते यह कार्रवाई नहीं होती, तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। स्थानीय ग्रामीणों ने मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि लंबे समय से वे इस समस्या को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। खबर के प्रसारण के बाद ही प्रशासन की नींद खुली और सड़क को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। लोगों ने उम्मीद जताई है कि आगे सड़क की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण तरीके से की जाएगी और केवल दिखावटी काम नहीं होगा।

सड़क मरम्मत के नाम पर लीपापोती

» कुसमी—महखोर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी की खुली पोल, जांच की मांग

लोकतंत्र की शान, रामबिहारी पांडेय ब्यूरो

सीधी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कुसमी से महखोर तक बनी सड़क इन दिनों ग्रामीणों के लिए राहत नहीं, बल्कि आफत बन चुकी है। सड़क की मरम्मत के नाम पर महज लीपापोती की गई है, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क में बड़े गड्ढों को ठीक करने के बजाय ऊपर-ऊपर छोटे गिट्टी डालकर काम निपटा दिया गया, जिससे बाइक सवार और छोटे वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर जगह-जगह गिट्टी बिछी हुई है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह सड़क बेहद खतरनाक साबित हो रही है। कई बार बाइक फिसलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कभी भी यहां कोई बड़ी घटना घट सकती है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सड़क मरम्मत में भारी लापरवाही और घटिया सामग्री उपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया है। गुणवत्ता की जांच किए बिना ही भुगतान कर दिया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि पूरा काम कागजों में दुरुस्त दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि इस सड़क पर पहले भी कई लोग एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं।

उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग

ग्रामीणों ने मांग की है कि कुसमी—महखोर रोड की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सड़क की दोबारा गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कर इसे सुरक्षित बनाया जाए, ताकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी नजर आए।इसके बावजूद न तो प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया और न ही सड़क को सुरक्षित बनाने की गंभीर कोशिश की गई। शिकायतें करने के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी सुनवाई नहीं करते, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है।

खंड प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि मीडिया की भूमिका जनहित के मुद्दों को सामने लाने में कितनी महत्वपूर्ण है। अब ग्रामीणों की मांग है कि गिट्टी हटाने के साथ-साथ सड़क की पूरी मरम्मत तकनीकी मानकों के अनुसार कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय हो, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो।

नाबालिगों से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व 25हजार के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला

» विशेष न्याायलय पॉक्सो एक्ट, सीधी ने सुनाया फैसला

लोकतंत्र की शान

सीधी। दादी के घर से अपने घर लौट रही पांच साल के अबोध बालिका को उठाकर जंगल मे ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी का आरोप प्रमाणित होने पर पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कठोर कारावास एवं 25हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय के अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी ने बताया कि अभियोक्त्री की मां के द्वारा इस आशय की देहाती नालशी अस्पताल चौकी सीधी में लेख करायी कि दिनांक 09.05.2023 को शाम करीबन 07:00 बजे वह घर के अंदर खाना बना रही थी। उसकी लड़की अभियोक्त्री उम्र लगभग 05 वर्ष पड़ोस में ही अपनी दादी के घर चली गई थी, जब काफी देर तक नहीं लौटी तो वह और उसके घर वाले उसे आस-पास टार्च लेकर ढूंढने लगे। ढूंढते हुए पास के जंगल में गये तो देखा कि उसके पड़ोस का केमलभान बैगा उसकी बच्ची को छोड़कर भाग रहा है। तब वह और उसके साथ के लोग दौड़कर बच्ची के पास गये और बच्ची से पूछा तो उसकी बच्ची ने बताया कि जब वह दादी के यहां से घर लौट रही थी तब केमलभान उसे गोद में उठाकर ले गया और जंगल में पत्थर में पटककर उसकी चड्डी उतार दिया था और अपनी छुन्नी (लिंग) उसके पेशाब के रास्ते में डाला था और उसका गला दबा रहा था, चिल्लाने नहीं दे रहा था। पटकने से उसकी लड़की की पीठ में खरोंचदार चोट आयी है और उसके पेशाब वाले रास्ते में खून निकल रहा था। उस समय लगभग रात्रि के लगभग 12-01 बज गये थे। केमलभान मौके से फरार हो गया था। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया था लेकिन वह मौके से भाग गया। फरियादी ने अभियोक्त्री को लेकर पुलिस चौकी खड्डी गयी थी तथा अभियोक्त्री का स्वास्थ्य ठीक न होने से उसे जिला अस्पताल सीधी लाया गया। उक्त पर से अस्पताल चौकी सीधी में जीरो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 0/2023 अंतर्गत धारा 363, 366, 376(ए)(बी) भा.दं.सं. एवं धारा 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दर्ज की गई तथा पश्चात् में थाना रामपुर नैकिन को उक्त बिना नंबरी नालशी प्राप्त होने पर थाना रामपुरनैकिन द्वारा असल अपराध क्र. 416/2023 में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। मामले की विवेचना निरी. सुधांशू तिवारी के द्वारा की गई है। मामले की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक एससी/12//2023 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशान्त कुमार पाण्डेय के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त केमलभान बैगा पिता रामलखन बैगा, उम्र 35 वर्ष, निवासी अंतर्गत थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र. को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा एवं 20,000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि रू. 25,000/- अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में क्षतिपूर्ति स्वरूप अभियोक्त्री को दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया। प्रकरण में न्यायालयीन संमंस/वारण्ट कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जारी किये गये।

स्वर्गीय सारिका भाटिया चेरिटेबल ट्रस्ट ने मनाया स्मृति सेवा संकल्प दिवस, मेधावी सम्मानित

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

करनाल। सारिका भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट (रजिस्टर्ड), मॉडल टाउन करनाल की ओर से बुधवार को स्वर्गीय श्रीमती सारिका भाटिया की पुण्य स्मृति में स्मृति (सेवा संकल्प) दिवस का भव्य, सुव्यवस्थित एवं गरिमामय आयोजन रघुनाथ मंदिर सभागार, सदर बाजार करनाल में किया गया। यह कार्यक्रम ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष समाज सेवा, शिक्षा प्रोत्साहन एवं सांस्कृतिक चेतना के उद्देश्य से नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों की सामूहिक प्रार्थना "इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना" से हुआ, जिसने पूरे सभागार को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इसके पश्चात बच्चों ने देशभक्ति गीत "देश मेरा रंगीला" सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया और देशप्रेम की भावना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत इस वर्ष रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चार मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनमें कक्षा दसवीं की सानिया एवं खुशी कुमारी, जबकि कक्षा बारहवीं के भूपेंद्र एवं बॉबी शामिल रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का यह प्रयास स्वर्गीय सारिका भाटिया को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर मंच से यह भी जानकारी दी गई कि सरिका भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट को उसकी निरंतर सेवाओं एवं सामाजिक योगदान के लिए देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का शुभकामना संदेश ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसे कार्यक्रम के दौरान सभी के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। कार्यक्रम के सांस्कृतिक सत्र में "मिले सुर हमारा तुम्हारा" समूह के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। सोनिया चोपड़ा ने "सत्यम शिवम सुंदरम", सी.ए. प्रवीण मित्तल एवं भाटिया भाटिया ने "आदमी मुसाफिर है", अरुण कांत ने "मधुबन खुशबू देता है", सतीश चावला ने "किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार" तथा वनीत भाटिया ने "जाने कहां गए वो दिन" जैसे सदाबहार गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, मंदिर कमेटी प्रधान बलदेव खेत्रपाल, प्रवेश शर्मा, संजय बठला, कृष्ण लाल तनेजा, विनोद खेत्रपाल, महेश चावला, सुरेंद्र बाबा, के.एल. अरोड़ा, अनिल भाटिया, सतपाल खेत्रपाल, अमित आहूजा, राखी तनेजा, राजेंद्र रामा मदान सहित शहर की अनेक प्रमुख हस्तियां शामिल रहीं। कार्यक्रम का प्रभावशाली मंच संचालन रंगकर्मी पवन शर्मा द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे आयोजन को एक सूत्र में पिरोते हुए संतुलित और सशक्त प्रस्तुति दी। समापन अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं एवं अतिथियों को लंगर प्रसाद एवं भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के पदाधिकारियों — विजय भाटिया (मुख्य संरक्षक), डा. आकांक्षा भाटिया (अध्यक्ष), डा. सार्थक भाटिया (उपाध्यक्ष), सी.ए. प्रवीण मित्तल (विधिक सलाहकार), राजेश भाटिया (कोषाध्यक्ष), सोनिया चोपड़ा (महासचिव), अलिप्त भाटिया (समन्वयक) एवं वीरेंद्र चोपड़ा (प्रकल्प प्रमुख) — की सक्रिय उपस्थिति एवं सहभागिता रही। अंत में सारिका भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार की ओर से सभी अतिथियों, कलाकारों, विद्यार्थियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी इसी भावना के साथ सेवा कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया।

संक्षिप्त समाचार

विमानवाहक पोत की ओर बढ़ रहा था ईरानी ड्रोन, अमेरिका ने हवा में ही किया नष्ट

वॉशिंगटन/मध्य पूर्व। अमेरिकी सेना ने अरब सागर में अपने विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार ड्रोन "आक्रामक तरीके" से पोत की ओर बढ़ रहा था और उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, जिसके बाद आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने बताया कि अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले एफ-35सी लड़ाकू विमान ने ड्रोन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही सैन्य उपकरणों को क्षति हुई। यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि समझौता न होने की स्थिति में हालात बिगड़ सकते हैं। इसी बीच, सेंट्रल कमांड ने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़े नौकाओं और एक ड्रोन ने अमेरिकी झंडे वाले एक व्यापारी जहाज के करीब तेज रफ्तार से पहुंचकर उसे रोकने और कब्जे में लेने की धमकी दी। विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां और तनाव आने वाले दिनों में अमेरिका-ईरान संबंधों को और संवेदनशील बना सकते हैं, खासकर तब जब दोनों देश बातचीत की संभावनाओं को भी टटोल रहे हैं।

समंदर में 4 घंटे तैरता रहा 13 साल का बच्चा, मां और भाई-बहन की जान बचाई

पर्थ। ऑस्ट्रेलिया में 13 साल के एक बच्चे ऑस्टिन एपलबी ने समुद्र में करीब 4 घंटे तैरकर अपनी मां और दो छोटे भाई-बहनों की जान बचाई। वह परिवार के साथ समुद्र में गया था। अचानक लहरें तेज हो गईं। बोट पलटने से सभी बहते हुए समुद्र में 14 किमी दूर निकल गए थे। द गॉर्जियन के मुताबिक, जोआन एपलबे अपने बच्चों ऑस्टिन, ब्यू और ग्रेस के साथ पर्थ से करीब 200 किलोमीटर दूर क्विंडलप में छुट्टियां मना रही थीं। शुक्रवार दोपहर वे समुद्र के किनारे पैडलबोर्ड के साथ पानी में खेल रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बच्चे थोड़ा दूर चले गए और तभी तेज हवा चलने लगी। हवा के कारण उनके चप्पू गिर गए और वे सभी धीरे-धीरे समुद्र में बहने लगे। हालात बहुत जल्दी खराब हो गए। जोआन को लगा कि अब किसी को मदद लाने के लिए किनारे जाना होगा। उन्होंने अपने 13 साल के बेटे ऑस्टिन को

चुना, क्योंकि उन्हें लगा वही सबसे मजबूत है। ऑस्टिन समुद्र में तैरकर मदद लाने निकल पड़ा। उस वक्त परिवार को लगा कि किनारा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे ऑस्टिन आगे बढ़ता गया, मां और बाकी बच्चे और दूर समुद्र में बहते चले गए। कुछ ही देर में वे ऑस्टिन को देख भी नहीं पा रहे थे। अंधेरा हो गया और लहरें तेज होती चली गईं। मां और बच्चे लाइफ जैकेट पहने पैडलबोर्ड को पकड़कर किसी तरह खुद को संभाले हुए थे। जोआन को लगने लगा कि शायद ऑस्टिन समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उधर ऑस्टिन लगातार तैरता रहा और करीब 4 किमी बाद किसी तरह किनारे पहुंचा। उसने बताया कि तैरते समय वह सिर्फ अपनी मां और भाई-बहन के बारे में सोच रहा था। किनारे पर पहुंचने के बाद वह 2 किमी दौड़कर फोन तक पहुंचा और शाम करीब 6 बजे इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया।

लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे की हत्या, घर में घुसकर गोली मारी, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे

त्रिपोली। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लीबियाई न्यूज चैनल फवासेल के मुताबिक जिंटान शहर में उनके घर पर चार हमलावरों ने हमला किया और उन्हें मार डाला। सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी के वकील खालिद अल-जैदी और राजनीतिक सलाहकार अब्दुल्ला ओथमान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी मौत की जानकारी दी। हालांकि शुरुआती बयानों में हत्या की वजह या हमलावरों की पहचान को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। सैफ अल-इस्लाम की मौत को लेकर उनकी बहन ने अलग ही दावा किया है। BBC ने लीबियाई टीवी के हवाले से बताया कि सैफ अल-इस्लाम की मौत लीबिया-अल्जीरिया सीमा के पास हुई। सैफ अल-इस्लाम की उम्र 53 साल थी। सैफ

अल-इस्लाम गद्दाफी को कभी अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जाता था। सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी को लंबे समय तक अपने पिता मुअम्मर गद्दाफी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता रहा। उनका जन्म 25 जून 1972 को त्रिपोली में हुआ। गद्दाफी परिवार लीबिया में दशकों तक सत्ता में रहा और सैफ अल-इस्लाम उसी ताकतवर परिवार का सबसे पढ़ा-लिखा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना-पहचाना चेहरा थे। उन्होंने लीबिया के बाहर भी पढ़ाई की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा ली। 2000 के दशक में वे खुद को एक सुधारवादी नेता के रूप में पेश करते थे। वे पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने, अर्थव्यवस्था और कुछ हद तक राजनीतिक बदलाव की बातें करते थे। इसी वजह से कई विदेशी नेता और मीडिया उन्हें गद्दाफी शासन का नरम और आधुनिक चेहरा मानने लगे थे। सैफ ने कभी कोई आधिकारिक पद नहीं संभाला, लेकिन वे लीबिया में अपने पिता के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। 2000 के दशक में उन्होंने लीबिया के पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई।

काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे विमान के इंजन में लगी आग, कोलकाता डाइवर्ट

काठमांडू। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल से तुर्की के इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने वाले तुर्किश एयरलाइंस के विमान के दाहिने इंजन में आग लगने की घटना सामने आई है। इसके बाद फ्लाइट को भारत के कोलकाता की ओर डायवर्ट कर दिया गया। विमानस्थल के महाप्रबंधक टेकनाथ सिटौला के अनुसार तुर्किश एयरलाइंस के विमान ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल से बुधवार दोपहर 1:28 बजे उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के चार मिनट के भीतर ही तुर्किश विमान के कप्तान ने दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना दी। इसके बाद चालक दल ने विमान को पश्चिम दिशा में मोड़ते हुए दाहिना इंजन बंद कर 10 से 12 मिनट तक होल्ड किया। उनके अनुसार तुर्किश एयरलाइंस का यह ए330-303 श्रृंखला का वाइड बॉडी विमान था, जिसमें कुल 225 यात्री सवार थे। दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना मिलते ही त्रिभुवन

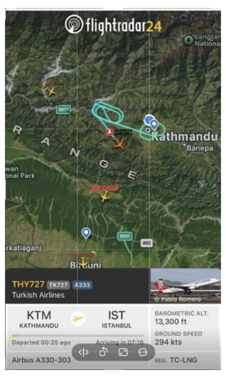

अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को एहतियातन 15 मिनट के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था। महाप्रबंधक सिटौला ने कहा कि इसके बाद दमकल, एंबुलेंस सहित सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं तैयार कर विमानस्थल को बंद कर दिया गया। इस बीच तुर्किश एयरलाइंस के चालक दल ने विमान को भारत के कोलकाता की ओर डायवर्ट करने की जानकारी दी। सिटौला के अनुसार आग लगते ही दाहिने इंजन को बंद करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। इसके बाद केवल बाएं इंजन के सहारे तुर्किश एयरलाइंस का विमान कोलकाता की ओर डायवर्ट किया गया। फिलहाल तुर्किश एयरलाइंस का वह विमान कोलकाता में सुरक्षित रूप से उतर चुका है। हमारा विमानस्थल भी अब सामान्य स्थिति में संचालित हो रहा है।

ग्रीस में कोस्ट गार्ड के जहाज की प्रवासी नाव से टक्कर, 15 की मौत

एजेंसी, एथेंस

ग्रीस और तुर्किये के मध्य स्थित एजियन सागर में चियोस द्वीप के तट पर ग्रीक कोस्ट गार्ड के एक गश्ती जहाज एवं प्रवासियों और शरणार्थियों को ले जा रही एक नाव के बीच टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 14 के शव समुद्र से बरामद किए गए। ग्रीक नेशनल ब्रॉडकास्टर ईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार, बचाए गए 24 प्रवासियों में से एक की पास के अस्पताल में चोटों के कारण मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में 11 पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं।

यह दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार रात लगभग 9:00 बजे हुई। घायलों में कई बच्चे और दो गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। दोनों महिलाएं चोट सह नहीं पाईं और कथित तौर पर गर्भपात हो गया। नेशनल इमरजेंसी एड सेंटर के अनुसार, बचाए गए ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आईं। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। इस अभियान में चार कोस्ट गार्ड जहाज, स्वयंसेवी गोताखोरों को ले जा रही एक निजी नाव और एक हेलेनिक वायु सेना का हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

ग्रीक के सरकारी रेडियो ईपीटी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, घायलों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। रात लगभग 12 बजे घायलों में से एक महिला को चियोस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में दस बच्चे हैं। इसी बीच, दो कोस्ट गार्ड अधिकारी भी घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ओइनौसेस के मेयर जियोर्गोस डैनियल ने कहा कि गश्ती जहाज ओइनौसेस में था। उसी ने प्रवासी नाव को देखा।

ग्रीक के समाचार आउटलेट प्रोटोथेमा की रिपोर्ट के अनुसार, चियोस का यह वाकया कोस्ट गार्ड और प्रवासी तस्करों के बीच हुई टक्कर का नतीजा है। कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज पर छोटी नाव पर सवार तस्करों ने ही पैंतरेबाजी करते हुए टक्कर मारी। इससे अफरातफरी मच गई। कोस्ट गार्ड की कार्रवाई में कई प्रवासी मारे गए। कई घायल हो गए। यह लोग मर्सिनिडी इलाके के बताए गए हैं। इस दौरान गोलीबारी की भी खबरें हैं। मगर इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि नाव में लगभग 35 लोग सवार थे।

सीहोर जिले के अमलाहा में 7 फरवरी को होगा दलहन क्षेत्र का राष्ट्रीय सम्मेलन

एजेंसी, भोपाल

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में 7 फरवरी को दलहन उत्पादन और उत्पादकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में दलहन क्षेत्र से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, मूल संवेदनाओं और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

राज्य के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बुधवार को बताया कि सम्मेलन में देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, दलहन अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, सरकारी बीज उत्पादक संस्थाएं, दाल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि तथा अन्य सहयोगी एजेंसियां भाग लेंगी।

मंत्री कंषाना ने कहा कि सम्मेलन के दौरान दलहन उत्पादन को सुदृढ़ करने, किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्नत तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दलहन क्षेत्र

- दलहन क्षेत्र में नीति निर्धारण और अनुसंधान में मील का पत्थर साबित होगा राष्ट्रीय सम्मेलन : कृषि मंत्री कंषाना

में नीति निर्धारण और अनुसंधान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मंत्री ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसानों तक नवीन शोध, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक खेती पद्धतियों और बाजार से संबंधित जानकारी पहुंचाना है, ताकि दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही विभिन्न राज्यों के अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर दलहन विकास के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी।

गुलमर्ग और पहलगाम में रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया

एजेंसी, श्रीनगर

कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम के पर्यटक रिसॉर्ट्स में रात का तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे गिर गया जबकि घाटी के बाकी हिस्सों में गर्म रात का आनंद लिया गया।

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 8.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जो मंगलवार रात की तुलना में 2.7 डिग्री कम है। पहलगाम, दक्षिण कश्मीर में एक पर्यटन स्थल जो अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है का तापमान शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री कम होकर शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। श्रीनगर में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसमी औसत से 3.6 डिग्री अधिक था।

मौसम विभाग के मुताबिक अन्य स्थानों में काजीगुंड का न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री, कोकेरनाग का न्यूनतम तापमान शून्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे और कुपवाड़ा का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में 40 दिनों तक चलने वाली सबसे कठोर सर्दियों की अवधि 'चिल्लई कलां' की समाप्ति के बाद से श्रीनगर में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है। तापमान में वृद्धि 20 दिवसीय 'चिल्लई खुर्द' (छोटी ठंड) में संक्रमण का प्रतीक है, जो 'चिल्लई कला' की समाप्ति के बाद शनिवार को शुरू हुई।

नेपाल में चुनावी हलचल बढ़ी, सेना ने संभाला मोर्चा

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल में पांच मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आज से सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। नेपाली सेना के समन्वय में निष्पक्ष चुनाव के लिए चारों सुरक्षा निकायों की तैनाती की जा रही है। नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को एकीकृत रूप से परिचालित किया जा रहा है। एकीकृत सुरक्षा योजना के अनुसार, चुनावी प्रयोजन के लिए भर्ती किए गए 'निर्वाचन पुलिस' को भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाएगा।

नेपाल पुलिस और निर्वाचन पुलिस मतदान स्थलों की भीतरी सुरक्षा करेगी। दूसरे स्तर की सुरक्षा घेराबंदी की जिम्मेदारी सशस्त्र प्रहरी बल की होगी। यह बल नेपाली सेना और नेपाल पुलिस के साथ समन्वय में कार्य करेगा। नेपाली सेना सुरक्षा घेराबंदी के बाहरी स्तर पर रहकर महत्वपूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारी संभालेगी। नेपाली सेना आज से सभी 165 निर्वाचन क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लेगी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने पिछले साल 27 नवंबर को प्रधानमंत्री की सिफारिश और मंत्रिपरिषद के निर्णय पर निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेपाली सेना की तैनाती को स्वीकृति प्रदान की थी। सेना के प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेत ने बताया कि चुनाव सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए आवश्यकता अनुसार सेना के 'बेस' स्थापित किए जाएंगे और जरूरत के आधार पर संयुक्त गश्त भी की जाएगी।

प्रवक्ता के अनुसार 80 हजार सैनिक चुनाव ड्यूटी में तैनात रहेंगे। इस दौरान हवाई अड्डों, कारागारों सहित महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नेपाली सेना संभालेगी। सेना के जिम्मे मतपत्रों की छपाई, मतपत्रों का परिवहन, मतदान स्थलों की सुरक्षा, मतपेटिकाओं का परिवहन तथा मतगणना स्थल की सुरक्षा शामिल है। इस बार कुल 3,406 उम्मीदवार मैदान में हैं। 18 जनवरी से चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है।

देशभर में 10,967 मतदान स्थलों पर 23,112 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह नेपाल पुलिस की ओर से चुनाव में 77 हजार जवानों की तैनाती की जाएगी। मौजूदा पुलिस बल निर्वाचन प्रबंधन के लिए अपर्याप्त होने के कारण एक लाख 33 हजार 'निर्वाचन पुलिस' की भर्ती की गई है। 2,845 मतदान स्थलों को सामान्य, 4,442 को संवेदनशील और 3,680 को अत्यंत संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है।

निर्वाचन के दौरान सशस्त्र प्रहरी बल की ओर से 34,576 कर्मी और 15,110 'निर्वाचन पुलिस' सहित कुल 49,686 जनशक्ति तैनात की जाएगी। सशस्त्र प्रहरी बल ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उच्च सतर्कता अपनाई गई है और किसी भी स्थिति में 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचने की व्यवस्था की गई है।

अन्नाद्रमुक ने जारी की दूसरे चरण की चुनावी घोषणाएं, पेंशन बढ़ाने, शिक्षा ऋण माफी, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वादा

एजेंसी, चेन्नई

तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) ने बुधवार को अपने दूसरे चरण की चुनावी घोषणाएं जारी कीं। पार्टी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में ये घोषणाएं चेन्नई के रोयापेट्टा स्थित अन्नाद्रमुक मुख्यालय में आयोजित जिला सचिवों की बैठक के दौरान की गईं। घोषणापत्र में सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। अन्नाद्रमुक ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके साथ ही विधवा महिलाओं, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को मिलने वाली सहायता राशि को वर्तमान 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने का वादा किया गया है। पार्टी ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों से लिए

गए शिक्षा ऋण माफ करने की घोषणा भी की है। इसके अलावा राशन कार्डधारकों को प्रति वर्ष तीन एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है। अन्नाद्रमुक ने तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जलीकट्टू को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की हैं। पार्टी के अनुसार, जलीकट्टू प्रतियोगिता के दौरान किसी खिलाड़ी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायल खिलाड़ियों के इलाज के लिए 2,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जलीकट्टू प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा भी की गई है। घोषणापत्र में वर्तमान ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पद्धति को पुनः लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिए गए ऋण माफ किए जाएंगे, जबकि दिव्यांगों द्वारा सहकारी संस्थाओं से लिए गए ऋण भी माफ करने का वादा किया गया है। इस अवसर पर एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से और भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि ऑटो चालकों ने भी अपनी मांगें पार्टी के समक्ष रखी हैं, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पलानीस्वामी ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का सिर आज गर्व से ऊंचा नहीं, बल्कि झुका हुआ और लटका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो, जब यौन हिंसा की कोई घटना सामने न आती हो। उन्होंने हाल ही में उत्तर भारत से आए एक प्रवासी मजदूर परिवार से जुड़े एक बच्चे, एक महिला और एक पुरुष की मौत का उल्लेख किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन

एजेंसी, भुवनेश्वर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा दौरे के तीसरे दिन बुधवार को पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व उन्होंने पारंपरिक पितृ कर्म भी संपन्न किए। पुरी पहुंचने पर राष्ट्रपति ने सबसे पहले श्वेतगंगा में पिंडदान किया, जो पितृ अनुष्ठानों से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। इसके बाद वह श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचीं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए।

मंदिर दर्शन के दौरान ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपटि और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। दर्शन के उपरांत श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से राष्ट्रपति को खंडुआ रेशमी वस्त्र और ओडिशा की पारंपरिक कला पट्टचित्र भेंट किया गया। इस पट्टचित्र में भगवान

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुरी में श्वेतगंगा में पिंडदान भी संपन्न किया

जगन्नाथ को केंद्र में रखते हुए दशावतार का सजीव चित्रण किया गया है।

राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। मंदिर में सुबह 10 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन स्थगित रहे, ताकि गोपाल वल्लभ भोग सहित सभी धार्मिक अनुष्ठानों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना के कई शिविरों पर कब्जा

एजेंसी, क्वेटा (बलोचिस्तान)

पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने घमासान के दौरान स्थापित किए गए पाकिस्तान की सेना के कई शिविरों और चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस बीच बीएलए के 31 जनवरी से शुरू ऑपरेशन हीरो के मद्देनजर प्रांत में संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। सरकार ने रेल और बस सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज नुश्की जिले के अहमदवाल इलाके में पाकिस्तान की सेना के शिविरों सहित कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अहमदवाल नुश्की शहर से 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा नुश्की से 34 किलोमीटर दूर स्थित गुलगौर में पाकिस्तान की सेना की चौकी को भी नियंत्रण में ले लिया है। बीएलए के लड़ाकों ने सेना के सभी हथियार और युद्ध सामग्री को हथिया लिया है।

बीएलए ने नुश्की समेत 12 शहरों में पाकिस्तान सेना के शिविरों और चौकियों पर एक साथ हमले किए हैं। नुश्की शहर के बाहरी हिस्से में बीएलए और सेना के बीच गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान के रेलवे विभाग ने क्वेटा से चमन तक चलने वाली घरेलू रेल सेवा को निलंबित करने की घोषणा की है। विभाग ने कहा है कि कराची से क्वेटा जाने वाली बोलन मेल सेवा 12 फरवरी तक निलंबित रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बलोचिस्तान से इंदौर मलिक और चमन तक चलने वाली ट्रेन सेवा के निलंबन के कारण विभाग को 30 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इस बीच पंजाब को बलोचिस्तान से जोड़ने वाला डीआई खान लोरालाई राष्ट्रीय राजमार्ग और क्वेटा से ताफ्तान जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी पांच दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।

संसद परिसर में राहुल गांधी-रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक

एजेंसी, नई दिल्ली

संसद परिसर में बुधवार को उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व सहयोगी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने बिट्टू को 'गद्दार' कहा तो जवाब में बिट्टू ने उन्हें 'देश का दुश्मन' करार दिया। यह घटना संसद के मकर द्वार के बाहर हुई जहां कांग्रेस सांसदों के निलंबन के विरोध में पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी निलंबित कांग्रेस सांसदों, जिनमें अधिकांश पंजाब से थे, उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए मकर द्वार के पास खड़े थे। इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुज़रे।

प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के मुताबिक, राहुल गांधी ने बिट्टू को देखते हुए कहा, "देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है। इसका चेहरा देखो।" इसके बाद उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा,

"नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे।" हालांकि, रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और पलटवार करते हुए कहा, "देश के दुश्मन..."। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बातचीत होती दिखी।

घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने पंजाब को आग में झोंक दिया था और गोल्डन टेंपल पर गोलियां चली थीं। उन्होंने कहा कि हजारों सिखों और पंजाबियों को निशाना बनाया गया। बिट्टू ने यह भी कहा कि जब तक वे कांग्रेस में थे, तब तक उन्हें शहीद का पोता कहा जाता था लेकिन भाजपा में आने के बाद उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को देश का मालिक समझते हैं और रोज़ सेना व राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं इसलिए उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया।

इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि एक सांसद और सम्मानित सिख नेता सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार' कहना शिष्टाचार, मर्यादा और गरिमा की सभी सीमाओं को पार करता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी आधार के किसी प्रतिष्ठित सिख नेता को गद्दार कहना न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि पूरे सिख समुदाय का अपमान है। संसद परिसर में हुई इस नोकझोंक के बाद सियासी बयानबाज़ी और तेज़ हो गई है और दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2026:- टैरिफ कटौती से संसद हंगामे तक, बॉन्ड मार्केट, सर्विस इकोनॉमी और बदलती वैश्विक शक्ति- संतुलन की कहानी-असल खेल क्या है?

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

» भारत-अमेरिका डील के जब पूरे दस्तावेज सार्वजनिक होंगे और उसके प्रभाव ज़मीन पर दिखेंगे, तब यह समझौता दूरगामी सफ़ल या चुनौती यह साबित होगा?

» भारत-अमेरिका समझौता वैश्विक वित्तीय प्रणाली,बॉन्ड मार्केट की संवेदनशीलता,डॉलर की शक्ति,और भारत की उभरती रणनीतिक हैसियत,इन सभी कारकों के संगम का परिणाम प्रतीत होता है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

US-इंडिया ट्रेड डील से किसे फायदा, सरकार ने क्या बताया?

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 2 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच हुई व्यापारिक सहमति ने वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर सीधे 18 प्रतिशत कर देना केवल एक व्यापारिक रियायत नहीं,बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, भू-राजनीति,वित्तीय अस्थिरता और घरेलू राजनीति के कई स्तरों को एक साथ उजागर करता है। यह डील जितनी अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराही जा रही है, उतनी ही भारत के भीतर विवादों और सवालों के घेरे में है।बजट सत्र के दौरान 4 फरवरी 2026 को हंगामा के कारण कार्यवाही को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था तथा पीएम को आज शाम पांच बजे से लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था, लेकिन सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि पीएम का संबोधन 5 फरवरी तक स्थगित किया जाना इस बात का संकेत है कि मामला केवल व्यापार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संप्रभुता और राजनीतिक रणनीति से जुड़ चुका है।इस समझौते को लेकर सबसे पहला और तीखा सवाल प्रक्रिया और पारदर्शिता का है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस डील की घोषणा भारत की संसद से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हुई।संसदीय लोकतंत्र में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है,तो उसकी पूरी जानकारी पहले संसद के पटल पर क्यों नहीं रखी गई। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने केवल एक संक्षिप्त बयान देकर औपचारिकता पूरी की, जबकि समझौते के मूल दस्तावेज़, शर्तें,अपवाद और सुरक्षा उपाय संसद से साझा नहीं किए गए।यह आपत्ति केवल राजनीतिक शोर नहीं है, बल्कि भारत की संसदीय परंपरा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।अतीत में चाहे डब्ल्यूटीओ समझौते हों, परमाणु करार हो या यूरोपीय संघ के साथ एफटीए,हर बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते पर संसद में विस्तृत चर्चा हुई है। ऐसे में विपक्ष का यह पूछना कि डील का टेक्स्ट आधारित विवरण क्यों नहीं दिया गया? लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के दायरे में आता है।विपक्ष इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और पारदर्शिता से जोड़कर देख रहा है, और यही कारण है कि संसद के भीतर विरोध इतना उग्र हुआ।दूसरा बड़ा विवाद कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर है। विपक्षी दलों का तर्क है कि टैरिफ कटौती का सीधा लाभ अमेरिकी कृषि उत्पादों,डेयरी और अन्य संवेदनशील वस्तुओं को मिलेगा, जिससे भारतीय बाजार में उनकी आसान एंट्री हो सकती है। भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संरचना का आधार है। छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पहले ही महंगाई, जलवायु परिवर्तन और बाजार अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा भारतीय किसानों को और कमजोर कर सकती है।इसी क्रम में विपक्ष ने ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। आरोप है कि भारत पर अमेरिकी तेल खरीदने का दबाव डाला गया, जिससे रूस से सस्ते तेल पर निर्भरता कम करनी पड़े। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने जिस तरह से डिस्काउंटेड रूसी तेल खरीदकर अपनी महंगाई और चालू खाते के घाटे को नियंत्रित किया, वह एक व्यावहारिक रणनीति मानी गई। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इस डील के तहत भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में किसी तरह का समझौता किया है, और क्या यह निर्णय आर्थिक विवेक से ज्यादा भू-राजनीतिक दबाव का परिणाम है। साथियों बात अगर हम विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर सरकार के जवाबों की करें तो,केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने संसद और मीडिया दोनों में आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि यह डील भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर की गई है और इसमें कृषि व दुग्ध क्षेत्रों की पूरी तरह रक्षा की गई है।गोयल के अनुसार यह कोई एकतरफा फैसला नहीं, बल्कि लगभग एक वर्ष तक चले गहन विचार- विमर्श और वार्ताओं कापरिणाम है,उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह टैक्स हटाने का मामला नहीं,बल्कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की रणनीति है जिससे भारतीय एमएसएमई, टेक्सटाइल, लेदर और समुद्री उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।वाणिज्य व उद्योग मंत्री का यह तर्क भी महत्वपूर्ण है कि 18 प्रतिशत का टैरिफ अमेरिका द्वारा कई अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में तुलनात्मक लाभ मिलेगा। सरकार इसे भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट-लेड ग्रोथ रणनीति के अनुरूप बता रही है।उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह नकारात्मकता फैला रहा है और संसद में चर्चा के नाम पर एक सटीक राजनीतिक स्टंट कर रहा है। साथियों बात अगर हम इस पूरे विवाद के पीछे अंदरूनी राजनीति की भूमिका की करें तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।2026 का साल राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और कई राज्यों में चुनावी माहौल बन रहा है। विपक्ष इस डील को कृषि,रोजगार और राष्ट्रीय हित से जोड़कर एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में पेश करना चाहता है।विदेशी दबाव के आगे झुकने का नैरेटिव भारतीय राजनीति में हमेशा प्रभावी रहा है,और विपक्ष इसी भावनात्मक धरातल पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।वहीं सरकार इस डील को वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत के प्रमाण के रूप में पेश कर रही है।भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका सर्विस सेक्टर और प्रशिक्षित युवा आबादी है।देश की लगभग 60-70 प्रतिशत युवा जनसंख्या तकनीकी रूप से प्रशिक्षित है, और आईटी, फिनटेक, एआई तथा डिजिटल सेवाओं में भारत की पकड़ विश्व स्तर पर मजबूत है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस क्षमता को पहचानती है। यही कारण है कि सेवा क्षेत्र भारत की सौदेबाजी की सबसे मजबूत पूंजी बना हुआ है। साथियों बात अगर हम भारत क़े आर्थिक आंकड़ों के स्तर पर स्थिति को समझने की करें तो, भारत की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है। भारत पर कुल कर्ज उसकी जीडीपी का लगभग 82 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका का कर्ज-जीडीपी अनुपात लगभग 126 प्रतिशत क़ेआसपास है।भारत के पास लगभग 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें सोने के साथ- साथ बड़ी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड भी शामिल हैं।अमेरिकी बॉन्ड की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अत्यधिक लिक्विडिटी है यानें जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत डॉलर में बदला जा सकता है। यही वह बिंदु है जहां वैश्विक वित्तीय राजनीति सामने आती है अमेरिका पर लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। यूरोप के पास इसके करीब 8 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड हैं। यदि बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉन्ड की बिक्री शुरू होती है, तो उनकी वैल्यू गिरती है और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ सकता है। ग्रीनलैंड विवाद और ब्रिटेन के हालिया वित्तीय संकट इसके उदाहरण हैं,जहां बॉन्ड बाजार की प्रतिक्रिया ने सरकारों को झुकने पर मजबूर कर दिया। पिछले एक साल में भारत ने लगभग 50-60 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड बेचे और उसकी जगह सोना खरीदा। इसी वजह से भारत का स्वर्ण भंडार लगभग 800 टन तक पहुंच गया, जिसमें करीब 100 टन की नई खरीद शामिल है। चीन ने भी इसी तरह करीब 200 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड बेचकर सोने में निवेश बढ़ाया है साथियों बात अगर हम अमेरिका क़े टैरिफ से पीछे हटाने और भारत के प्रति नरम रुख को समझने की करें तो इस वैश्विक ट्रेंड का नतीजा है कि सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। यह स्थिति अमेरिका के लिए चेतावनी की घंटी है, क्योंकि यदि यह प्रवृत्ति तेज होती है तो डॉलर और बॉन्ड बाजार में अस्थिरता आ सकती है।इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप प्रशासन के टैरिफ रुख में नरमी को देखा जा रहा है। यह केवल भारत के साथ संबंध सुधारने का प्रयास नहीं, बल्कि अमेरिकी वित्तीय स्थिरता को बचाने की रणनीति भी हो सकती है। माना जा रहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन युद्ध के संभावित अंत पर भी चर्चा हुई। यदि युद्ध समाप्त होता है, तो पहले से लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ का औचित्य कमजोर पड़ जाता। ऐसे में भारत के साथ समझौता कर टैरिफ को 18 प्रतिशत तक लाना अमेरिका के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से सुविधाजनक कदम हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह डील यूरोपीय संघ के साथ हुई मदर ऑफ ऑल डील्स से बेहतर है? इसका उत्तर सीधा नहीं है। यूरोपीय संघ के साथ समझौता अधिक व्यापक और संरचनात्मक है, जबकि अमेरिका के साथ यह डील ज्यादा रणनीतिक और समय-सापेक्ष है। दोनों की प्रकृति अलग है, लेकिन भारत के लिए दोनों ही आवश्यक हैं,एक बाजार विविधीकरण के लिए, दूसरा वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए। अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2026 केवल टैरिफ कटौती का मामला नहीं है।यह लोकतांत्रिक पारदर्शिता, घरेलू राजनीति, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और भू- राजनीतिक समीकरणों का संगम है। विपक्ष के सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए जरूरी हैं,जबकि सरकार का तर्क आर्थिक अवसरों और रणनीतिक लाभों पर आधारित है।सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। आने वाले समय में जब डील के पूरे दस्तावेज़ सार्वजनिक होंगे और उसके प्रभाव जमीन पर दिखेंगे, तब यह स्पष्ट होगा कि यह समझौता भारत के लिए कितनी दूरगामी सफलता या चुनौती साबित होता है।

-संकलनकर्ता लेखक-कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

काम व शरीर को ठीक करने हेतु शांति जरुरी

लेखक- संजय गोस्वामी

आज मोबाइल के युग में मन में अशांति रहती है हमारी आँखें प्रतिपल संसार में पूर्णता खोज रही हैं यही कारण है कि मन इतना अशांत रहता है, जब तक मन उस एक को नहीं पा लेगा जिसकी उम्मीद वो संसार से रखता है तब तक अशांति बनी रहेगी,अशांति तो मन में ही होती और उसी को जागरूक करना होता है और मन शांत हो जाए तो आन्तरिक शांति आ जाती है। फिर भी अशांत व्यक्ति के लिए कहने में तो यही आता है कि रेस्ट लेस बॉडी है। यह सही है क्योंकि राम का नाम को बोलने से हमारी स्टेटिक एनर्जी और डायनामिक एनर्जी दोनों सक्रिय होते हैं उसके पश्चात आप भगवान राम को जब जोड़ देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को स्टैटिक ऊर्जा की ओर एक प्रकार से बढ़ाने का प्रयास करते हैं जो स्थायित्व देता है। और हृदय में यह गूंज स्वाभाविक है। क्योंकि यह राम नाम का तरंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर को आंदोलन करती है और हमारा मस्तिष्क ध्यान करने पर अपनी सुग्रहता को बढ़ा देता है जिस कारण हमको यह गूंज वहां सुनाई देती है। इस मानव के शरीर में तो प्रभु राम ने बहुत कृपा की है। बॉडी के अंदर रिपेयर सिस्टम है साधारणतय यह कृपा बड़े बड़ों के ऊपर नहीं की जाती है। इसकी अनुभूति बार-बार होती है भगवान राम का ध्यान करने से अब चाहे कोई द्वैत बोले अद्वैत बोले कोई भी बोले वह सब तर्क वितर्क की बातें हैं लेकिन जहां अनुभूति की बात होती है बहुत से लोग मन की चाल बाजियां कह सकते हैं, कहते रहे लेकिन जो प्रभु राम की लीला की कृपा होती है उस पर मैं बार-बार बलिहारी होता हूं। जिस तरीके से प्रश्न को और जिज्ञासा को समझाया जाता है वह वैज्ञानिक आधार पर खराब उतरता है और स्वयं मुझे संतुष्ट करता है यह केवल और केवल प्रभु की कृपा ही है अब ज्ञानी जान भले ही कुछ भी भाषण देते रहे बोलते रहे समझाते रहे, चमत्कार दिखाते रहे लेकिन उनको समझने का मन नहीं करता है क्योंकि जब ईश्वर राम स्वयं समझाता है अंदर से बोली आती है तो मन धन्य हो जाता है। मन द्रवित हो जाता है प्रभु की कृपा देखकर जिस तरह के गुण संस्कार उसके उसके माता पिता समाज से मिलते हैं वह उसी गुण को धारण करता है और वही वर्ण बन जाता है संस्कृत धातु भज् (bhaj) का मुख्य अर्थ सेवा करना, पूजा करना, आराधना करना या भक्ति करना है, जिससे भक्ति और भजन शब्द बने हैं।जो भी भगवान राम की भक्ति करता है उसमें सेवा का भाव आता है जो भक्ति का ही अंग है । सेवा एक बहुत सुंदर आराधना का रूप है । भजन जिसमें प्रभु राम का स्मरण करते हैं। सेवा कर्मों से प्रभु का स्मरण है । कौन हिस्सा होगा यह जिनकी योजना है वहीं चयन करते हैं। लीला रचाते हैं। हिस्सा बनना है तो उनकी (भगवान राम की) शरण में जाओ। प्रार्थना करो। शरणागति सुदृढ़ बनाओ। जीव दशा से मुक्त होने का प्रयास बढ़ाओ। हम सब हिस्सा ही हैं इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सबको काम सौंपे हैं आप देख नहीं रहे किसान, मजदूर,पत्रकार ,शिक्षक सबको काम मिला है कि नहीं संसार का हिस्सा सब है। महाभारत में दुर्योधन आदि भी हिस्सा ही थे। लेकिन स्तर अलग अलग हो सकते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भगवान राम के युग कार्य का हिस्सा बनो। उनके यंत्र बनो। : ईश्वर के यंत्र ही हम सब वो अलग बात है कि किसी को पता रहता है किसी को नहीं किसी पंखे को भान रहता है कि मुझे लाइट चला रही है और कोई समझता है मैं स्वयं चल रहा हूं विज्ञान की अपनी मर्यादा है विज्ञान पूछता है: "यह कैसे होता है?" विज्ञान: जाँचता है, प्रयोग करता है और प्रमाण मांगता है। लेकिन विज्ञान यह नहीं बताता: जीवन का अंतिम अर्थ क्या है। सही–गलत कैसे तय करें। भगवान राम की साधना मर्यादा का पालन करना है साधना सिखाती है: "मैं कौन हूँ? दुख क्यों है? शांति कैसे मिले?" लेकिन हर अनुभव हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। इसलिए आध्यात्म को "फुल-प्रूफ विज्ञान" बनाकर बेचना गलत है। जब तक भगवान राम के अर्थ को हम समझ नहीं पाते तब तक हम मौन और शांत रूप प्राप्त नहीं होंगे तब तक में कोई भी चर्चा निरर्थक कहीं जा सकती है। राम को पाना ही यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है।गौतम ऋषि की पत्नी को इंद्र के छल के कारण गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बनी और भगवान राम के चरण स्पर्श से पुनः जीवित हो गईं एक मात्र ईश्वर भगवान राम है जो यह बताता है कि भगवान राम जे चरण स्पर्श मात्र से पत्थर जो निर्जीव है वो भी सजीव हो जायेगा कठोर कठोर चीज भी चरण स्पर्श मात्र से पिघल कर राम के भक्ति में लीन हो जायेगा।

मताधिकार के साथ निर्वाचित होने के अधिकार पर जनमत निर्माण का समय

राजेश पाठक

भारत का संविधान के अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब कोई भी सामान्य नागरिक 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता है। इस क्षमता से वह अपने नेतृत्वकर्ता को चुन सकता है। जब किसी व्यक्ति में सही-गलत में अंतर करने की क्षमता इस उम्र में प्राप्त हो गई मान ली जाती है तो उन्हें स्वयं नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने के लिए अर्थात् लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं के सदस्य बनने के लिए अगले न्यूनतम 7 वर्षों तक और किस अनुभव के लिए इंतजार कराया जाता है? मेरा मानना है कि जब किसी व्यक्ति में नेतृत्वकर्ता को चुनने की क्षमता विकसित है तो उसमें नेतृत्व करने की क्षमता से इंकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जब किसी व्यक्ति को मत देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है ठीक उसी समय उसे निर्वाचित होने का भी अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए।इस संबंध में तर्क यह है कि किसी को किसी उद्देश्य के लिए चुनना एक तार्किक एवं अनुभवजनित विधा है जिसमें स्वयं ही अनुभव एवं आंतरिक/बाह्ज्ञान तथा सकारात्मक परिकल्पना की आवश्यकता होती है और जब हमारा संविधान यह स्वीकार करता है कि किसी खास उम्र यानी 18 वर्ष में लोगों में परिपक्वता एवं अनुभव क्षमता विकसित है तो उन्हें स्वयं भी उसी उम्र में चुने जाने का अधिकार क्यों नही ? इसलिए यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हमें अच्छे-बुरे, देशहित-स्वहित आदि में अंतर करने की क्षमता लेकर चयन करने की शक्ति प्राप्त है तो स्वयं ही उसी उम्र में चुने जाने के अधिकार से क्यों वंचित रहें ? इतना ही नहीं अगर हम आपराधिक कृत्य की बात करें तो पता चलता है कि अब तो न्यायिक प्रक्रिया एवं व्यवस्था भी बाल अपराध की श्रेणी में मान्य उम्र को और भी घटा देने पर समुचित विचार कर रही है, उसे तो और भी लगने लगा है कि लोगों में परिपक्वता 18 वर्ष की उम्र से बहुत पहले ही आ जाती है।अतः यह मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होते ही हमें वयस्क मानते हुए मताधिकार प्रदत्त किया जाता है एवं हम देश/ राज्य के भाग्यविधाता को चुनने में संवैधानिक तौर पर अधिकृत हो जाते हैं। जो लोग यह तर्क देते हैं कि चुने जाने के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य अन्य क्षेत्रों में परिपक्वता का होना बहुत जरूरी है जो कि सामान्यतया 25 वर्ष की उम्र होते-होते लोगों को प्राप्त हो जाती है तो उस अनुभवजनित योग्यता से संबंधित आधार को उम्मीदवार होने की योग्यता में ही क्यों नहीं शामिल कर लिया जाता है कि वयस्क मताधिकार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष प्राप्त करने के बाद कम से कम सात वर्षों तक उन्हें और भी ज्ञानार्जन करना चाहिए ताकि देश/राज्य को परिपक्व एवं अनुभवी नेतृत्वकर्ता मिल सके। इस संबंध में दूसरा तर्क यह है कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में चुने जाने की वास्तविक क्षमता या फिर योग्यता नहीं प्राप्त करता है अर्थात चुने जाने हेतु वह अपरिपक्व नागरिक है तो फिर उसे देश/राज्य के सही नेतृत्वकर्ता को चुनने में परिपक्व नागरिक कैसे माना जा सकता है? मुझे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि देश/राज्य के राजनीतिक या अन्य प्रशासनिक क्रियाविधि हेतु योग्यता के साथ-साथ अनुभव भी आवश्यक कारक है तो फिर क्या बिना कोई सक्रिय क्रियाकलापों के ही सिर्फ 25 वर्ष की उम्र प्राप्त हो जाने से उस नागरिक को राजनीति या अन्य मामलों में अनुभवी मान लिया जाना चाहिए जो कि सामान्यतया उसे चुने जाने के अधिकार को संपुष्ट कर देता हो क्योंकि विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने हेतु किसी ढंग के राजनीतिक या अन्य अनुभवों को तो अनिवार्य नहीं बनाया गया है।यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि समाज या उसके अंतर्गत गठित किसी संस्था-समूह के अंतर्गत नेतृत्व कर चुके व्यक्ति को ही वृहत्तर नेतृत्व करने का विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इससे देश/राज्य को एक अनुभवी नेतृत्वकर्ता प्राप्त हो सकेगा एवं उनके अनुभवों एवं गुणों का लाभ पूरे राज्य/देश को प्राप्त हो सकेगा। यह अपने देश की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए हास्यास्पद ही प्रतीत होता है कि बिना किसी सांगठनिक नेतृत्व क्षमता एवं कोरा अनुभव के, मात्र सहानुभूति या इससे जुड़े अन्य मापदण्ड अपने देश में नेतृत्वकर्ता के चयन में प्रभावी भूमिका निभाती रही हैं जो कि देश एवं राज्य के अपरिपक्व प्रजातंत्र होने के संपूर्ण कारण को परिलक्षित करता है। उपर्युक्त तथ्यों को अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि चुनने और चुने जाने के बीच जो सात वर्षों का गैप या अंतर है वह बेमानी है। यह गैप या अंतर यह प्रमाणित करने में सर्वदा विफल रहा है कि इस अंतर से इतनी क्षमता एवं इतनी परिपक्वता आ जाती है जो कि देश/राज्य के नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है और उसके ठीक विपरीत 18 वर्ष की उम्र में वही क्षमता एकदम नहीं विकसित होती है। उपर्युक्त संदर्भ में सरकार के पास दो विकल्प रह जाते हैं जिनमें से, आज की बदली हुई परिस्थितियों में, एक का चयन किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है।प्रथम तो यह है कि जिस उम्र में कोई नागरिक वयस्कता को प्राप्त करता है एवं लोकसभा/विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्राप्त करता है तो ठीक उसी वक्त से उसे चुने जाने का भी अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरे, यदि चुने जाने में कोई विशेष योग्यता, अनुभव, तर्क या विलक्षणता की आवश्यकता देश एवं राज्य के प्रशासनिक हित में दृष्टिगोचर होता है तो उक्त प्राप्त अनुभव का साक्ष्य संग्रहण हो एवं वस्तुतः चुनाव लड़ने की आवश्यक अर्हताओं में इसे आवश्यक रूप से शामिल की जाय। इस ढंग के अनुभव एवं क्रियाशीलता के उदाहरण हो सकते हैं-छात्र संगठन या अन्य दबाव समूह के सक्रिय कार्यकर्ता या पदाधिकारी, किसी एन जी ओ का पदधारी जो समाज या राज्यहित साधने में अपनी उर्जा लगाते हैं या कोई अन्य राजनीतिक, सामाजिक सांगठनिक अनुभव जो नेतृत्व के गुणों का धारण करता हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि दबाव समूह के सदस्यों का राजनीतिक दलों के समान राजनीतिक हित साधने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है तथापि जब वे किसी राजनीतिक दल के आधर पर चुनाव लड़ना चाहें तो उन्हें दबाव समूह के सदस्यों के रूप में सक्रियता समाप्त कर देनी चाहिए ताकि दबाव समूह के सार तत्व को अक्षुण्ण रखा जा सके। परंतु उपर्युक्त दो विकल्पों में किसी भी एक विकल्प का अनुसरण नहीं किया जाना सरकार की अन्य/ इतर मनसा को दर्शाता है जिसे आज का आधुनिक समाज सहजता से स्वीकार करने में असहज महसूस कर रहा है। जनप्रतिनिधियों को चुनने एवं स्वयं जनप्रतिनिधि चुने जाने के बीच के काल को हम अर्द्धनागरिकता या नागरिकता गैप की संज्ञा दे सकते हैं क्योंकि उन्हें जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार तो संवैधानिक तौर पर प्राप्त होता है परंतु वे स्वयं जनप्रतिनिधि बनने के दावेदार नहीं हो सकते।जनप्रतिनिधियों की औपचारिक योग्यता को लेकर देश में हमेशा बहस छिड़ती रही है एवं सामान्य तथा विशिष्ट तौर पर इस तर्क को सर्वदा झुठलाते रहा गया है कि उन्हें औपचारिक योग्यता वाला होना चाहिए परंतु यदि उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त न भी हो तो इतना तो आवश्यक है ही कि उन्हें समाज में नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों से युक्त होना चाहिए जिसकी आवश्यकता स्वीकारी जाती रही है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अगर आवश्यकता हो तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धराओं में आवश्यक संशोधनोपरांत लोकसभा/विधानसभा के सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की आवश्यक अर्हताओं में भले ही औपचारिक शैक्षणिक योग्यता, किसी खास सीमा तक, को समावेशित नहीं किया जाय तथापि राजनीतिक, सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्राप्त औपचारिक अनुभवों को उनकी अर्हता में आवश्यक रूप से समावेशित किया जाना चाहिए। ऐसा समावेश भले ही प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक जे.एस. मिल द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए निर्धारित औपचारिक योग्यता का हूबहू अनुसरण नहीं करता हो तथापि अनुभवजन्य योग्यता का निर्धारण किए जाने से बहुत हद तक उनकी आत्मा के करीब हम अपने को पहुंचा सकते है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि जनप्रतिनिधियों को चुने जाने के लिए निर्धारित अर्हताओं में उतना तो होना ही चाहिए कि उन्हें सामान्य ज्ञान एवं अंकगणित जैसे व्यावहारिक विषयों का ज्ञान हो । उपर्युक्त सुझाए गए उपायों को अगर हम नकार भी देते हैं तो इस संवैधानिक सच से कैसे इंकार किया जा सकता है कि भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जब वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गयी थी तब उस वक्त भी निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष ही रखी गयी थी जबकि हम तटस्थ भाव से अध्ययन करें तो उसी वक्त निर्वाचित होने के लिए कम से कम समानुपातिक ढ़ंग से न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष तो कर ही दी जानी चाहिए थी जो कि आज तक नहीं हुआ। वास्तव में देखा जाए तो यह विषय अत्यंत ही संवैधानिक महत्व एवं जनहित का है। अब इसे प्रजातांत्रिक दुविधा का शिकार होने से बचाने के लिए स्पष्ट जनमत निर्माण की आवश्यकता है।

(लेखक झारखंड सरकार के योजना एवं विकास विभाग में सांख्यिकी अधिकारी हैं)

नारी देह, नारी अधिकार: माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

लेखक - ललित गर्ग

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता। विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि "माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है" इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है। न्यायालय ने शिक्षा को एक 'मल्टीप्लायर राइट' बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में "मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर" स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे ।

विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में आज आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की खिताबी जंग

वडोदरा (एजेंसी)। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। लीग के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहकर आरसीबी ने सीधे फाइनल में एंट्री मारी थी। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर रही गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एलिमिनेटर खेला गया। इसमें जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से जीत हासिल करके फाइनल का टिकट कटाया। दिल्ली की टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है तो आरसीबी का दूसरा खिताबी मुकाबला होगा। स्मृति मंधाना आरसीबी की कप्तान हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताबी मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाएगा। यह मैच वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर होना है। मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर होगी। इसके लिए टॉस 7 बजे होगा। दिल्ली अभी तक एक बार भी लीग को नहीं जीत पाई है। आरसीबी ने दिल्ली को ही हराकर 2024 सीजन अपने नाम किया था।

आरसीबी को हरा चुकी दिल्ली

इस सीजन आरसीबी ने दमदार खेल दिखाया है। लीग राउंड में टीम ने लगातार 5 मैच जीतकर प्लेऑफ में एंट्री मारी थी। दिल्ली कैपिटल्स ही वह टीम थी जिसने आरसीबी को विजयी रथ को रोका था। सीजन के 15वें मैच में दिल्ली ने आरसीबी को 7 विकेट से मात दी थी। वह मुकाबला भी वडोदरा में ही खेला गया था। दोनों टीमों के बीच अभी तक 9 मुकाबले हुए हैं। इसमें दिल्ली ने 6 जीते हैं जबकि आरसीबी के खाते में तीन मैच आए हैं।

इस प्रकार हैं दोनों टीमें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु– ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, प्रेमा रावत, सयाली सतघरे, लॉरेन बेल, प्रथ्योषा कुमार, अरुंधति रेड्डी, दयालन हेमलता, पूजा वस्त्राकर, लिन्से स्मिथ।

दिल्ली कैपिटल्स– शैफाली वर्मा, लिजेल ली (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमाह रोड्रिग्स (कप्तान), मारिज़ेन कप्प, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, लुसी हैमिल्टन, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, मिन्नू मणि, तानिया भाटिया, अलाना किंग, चिनेले हेनरी, प्रगति सिंह, एडडला स्रुजाना।

सुप्रीम कोर्ट बोला-जिन्हें बैट पकड़ना नहीं आता, वे क्रिकेट संघों में

● खेल की पहचान सिर्फ खिलाड़ियों से, महाराष्ट्र एसोसिएशन चुनाव पर रोक हटाने से इनकार

नईदिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट और अन्य खेल संघों के संचालन पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि खेल संस्थाओं का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए, जो खेल को समझते हों। क्रिकेट संघों में रिटायर्ड क्रिकेटरों को जगह मिलनी चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जो बैट तक पकड़ना नहीं जानते। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की नेतृत्व वाली बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के चुनाव पर रोक लगाई गई थी। ये चुनाव 6 जनवरी को होने थे, लेकिन उनमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लगे थे।

सीजेआई ने एमसीए में अचानक से सदस्य बढ़नें पर सवाल उठाया– सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एमसीए की सदस्यता में अचानक हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया। कोर्ट ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि 1986 से 2023 तक एसोसिएशन में 164 सदस्य थे,

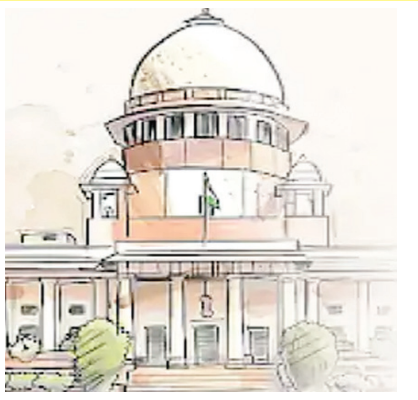

लेकिन इसके बाद अचानक बड़ी संख्या में नए सदस्य जोड़ दिए गए।

सीजेआई ने पूछा कि इतने सालों में सीमित सदस्य और फिर अचानक 'बंपर ड्रॉ' कैसे हो गया। उन्होंने कहा- अगर सदस्य संख्या 300 तक बढ़ानी थी तो उसमें नामी और रिटायर्ड अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए था।

एमसीए और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रक्रिया देखी थी और कुछ आवेदनों को खारिज भी किया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि चैरिटी कमिश्नर ने बिना कैबिनेट से सलाह लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया।

केदार जाधव ने वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया था– मामला तब शुरू हुआ जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा नेता केदार जाधव ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 401 नए सदस्यों को जोड़कर वोटर लिस्ट में हेरफेर की गई। याचिका में कहा गया कि इनमें से कई लोग एनसीपी-सपा विधायक रोहित पवार के रिश्तेदार या कारोबारी सहयोगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी और सभी आपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखने को कहा।

13 फरवरी से शुरू होगा 'दिल्ली खेल महाकुंभ', 16 स्टेडियम समेत कई वेन्यू पर मैच

नई दिल्ली(एजेंसी)। खेल संस्कृति को बढ़ाने की दिशा में दिल्ली सरकार 'दिल्ली खेल महाकुंभ ' प्रतियोगिता करवाएगी। खेल और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसका उद्घाटन 13 फरवरी को मुख्यमंत्री रेख गुप्ता करेंगी। प्रारंभिक चरण में इसमें कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्क्वैश- इन सात खेलों को शामिल किया गया है।

इनमें 20 हजार से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। यह महाकुंभ एक महीने तक दिल्ली के 16 विभिन्न स्टेडियम और अलग-अलग वेन्यू जैसे बवाना, विकासपुरी, नजफगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में रखा जाएगा ताकि हर क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर मिल सके। इस अवसर पर सूद ने 'रणवीर'नाम से 'दिल्ली खेल महाकुंभ' के मैस्कॉट का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि रणवीर दिल्ली के युवाओं की ऊर्जा, साहस और खेल भावना का प्रतीक है।जीतने वाली टीमों और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जीतने वाले खिलाड़ियों को क्या इनाम मिलेगा?

भारत में नहीं दिखेंगे पीएसएल के मैच

पाक ने टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच रोके मीडिया राइट्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने के बाद एक और भारत विरोधी कदम उठाया है। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (पीएसएल 2026) के 11वें सीजन के मैचों का भारत में प्रसारण करने पर रोक लगा दी है। पीसीबी ने पीसएल11 के मैचों के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचते हुए यह कदम उठाया है। हालांकि इससे उल्टा पाकिस्तान को ही नुकसान होने की संभावना मानी जा रही है, क्योंकि क्रिकेट मैचों में विज्ञापन देने वाली अधिकतर कंपनियां भारतीय हैं और भारत में करीब 140 करोड़ की आबादी में से 80 फीसदी क्रिकेट मैचों का बड़ा दर्शक वर्ग है।

पाकिस्तानी कंपनी ने ही खरीदे हैं अधिकार– मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल 11 के ग्लोबल मीडिया राइट्स के लिए बोली मांगी थी, जिसमें वली टेक्नोलॉजीज सबसे बड़ी बोलीदाता के तौर पर सामने आई है। पीसीबी ने भारत में प्रसारण के अधिकार छोड़कर बाकी सभी जगह के राइट्स वली टेकनोलॉजीज को एक साल के लिए दिए हैं। वली टेक्नोलॉजीज खुद को ' मेड इन पाकिस्तान ' टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाली कंपनी होने का दावा करती है।

पिछली बार से 149 प्रतिशत ज्यादा महंगी कीमत का दावा

पीएसएल के सीईओ सलमान नासिर ने कहा, वली टेक्नोलॉजीज ने पिछले साल के मुकाबले 149 प्रतिशत ज्यादा कीमत पर ग्लोबल मीडिया राइट्स खरीदे हैं, जो पीएसएल की बढ़ती ब्रांड वैल्यू और इंटरनेशनल डिमांड को दिखा रहे हैं। हम नया बेंचमार्क तय करने के लिए वली टेक्नोलॉजीज के आभारी हैं।

क्रिकेट के 73 नियम बदले 1 अक्टूबर से लागू होंगे

● टेस्ट में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो नया बैटर आएगा, लेमिनेटेड बैट को मंजूरी

मेलबर्न (एजेंसी)। क्रिकेट के 73 नियम बदल दिए हैं। इनमें टेस्ट मैच में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर पूरा ओवर खेलना अनिवार्य कर दिया गया है। डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाउंड्री पर लिए जाने वाले कैच, विकेटकीपर की पोजीशन जैसे कई नियम बदले गए हैं। लेमिनेटेड बैट को सशर्त मंजूरी दी गई है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। 2022 के बाद नियमों में यह सबसे बड़ा अपडेट है।

बदले गए मुख्य नियम

1. टेस्ट मैच में दिन का आखिरी ओवर का नियम बदला– क्रिकेट नियम बनाने वाले मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने अपनी वेबसाइट पर बताया

कि टेस्ट मैचों में दिन का आखिरी ओवर अब हर हाल में पूरा कराया जाएगा। ऐसा न होने से खेल का रोमांच कम हो जाता है। एमसीसी ने कहा, 'यह अनुचित माना गया कि अगर दिन के अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रही टीम विकेट लेती है, तो बल्लेबाजी टीम को नया बल्लेबाज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती।' वहीं यह भी बयान में कहा गया कि, इससे समय की बचत भी नहीं होती, क्योंकि बची हुई गेंदें अगले दिन पूरी करनी ही पड़ती हैं। साथ ही इससे खेल का रोमांच कम हो जाता है। नया बल्लेबाज मुश्किल परिस्थितियों से बच जाता है। क्योंकि आमतौर पर उस समय गेंदबाजों के लिए हालात अनुकूल होते हैं। नए नियम के तहत अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो अंतिम पूरा किया जाएगा, भले ही उस दौरान विकेट गिर जाए।

ओवरथ्रो और 'डेड बॉल' की नई परिभाषा– एमसीसी ने ओवरथ्रो और मिसफील्ड के बीच के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। अब ओवरथ्रो सिर्फ तभी माना जाएगा, जब कोई फील्डर विकेट पर गेंद फेंकता है और वह गेंद आगे निकल जाती है।

पीएफ के ब्याज दर में कटौती की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारियों के लिए बड़ी बचत योजना माने जाने वाले भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर में हल्की कटौती कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओकी ओर से ब्याज दर को 8 फीसदी से 8.20 फीसदी के दायरे में रखा जा सकता है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह दर 8.25 फीसदी तय की गई थी। इस फैसले पर अंतिम मुहर ईपीएफओ की 239वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लग सकती है, जो मार्च के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। हालांकि, इस बार ब्याज दर को लेकर फैसला इतना आसान नहीं माना जा रहा है। वजह है आगामी चुनाव। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को राहत देने के लिए लगातार तीसरे साल ब्याज दर में कोई बदलाव न करे और इसे 8.25 फीसदी पर ही बरकरार रखा जाए। बीते कुछ वर्षों से ईपीएफओ ने ब्याज दरों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं किया है।

विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए सेबी का बड़ा प्लान

30 की जगह 5 दिन में होगा यह काम

नईदिल्ली, एजेंसी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय शेयर मार्केट से दूर हो रहे विदेशी निवेशकों को रिझाने का एक प्लान बनाया है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा है कि बाजार नियामक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा काफी कम करने की योजना बना रहा है। पांडेय के अनुसार, लक्ष्य है कि यह प्रक्रिया केवल 5 दिनों में पूरी हो, जबकि वर्तमान में इसके लिए 30 दिनों का प्रावधान है। हालांकि, लोगों की धारणा है कि इसमें कई महीने लग जाते हैं।

विदेशी निवेशकों को और आकर्षित करने के लिए, सेबी उन्हें भारतीय बाजारों में प्रवेश करने के तरीके समझाने के लिए वेबिनार आयोजित कर रहा है ताकि उनकी ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया आसान और तेज हो। पांडेय ने बताया कि सेबी अधिकारियों द्वारा आयोजित ऐसे वेबिनार में लगभग 2,000 एफपीआई शामिल हुए हैं। नियामक भारतीय पूंजी बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना चाहता है, क्योंकि हाई वैल्युएशन और कमजोर कमाई जैसे कारण निवेशकों के रुख को प्रभावित कर रहे हैं। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में एफपीआई ने शेयर बाजार से 1.66 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी, जबकि एक साल पहले उनका 427 करोड़ रुपये का निवेश आया था।

कैपिटल गेन टैक्स एक चुनौती

हालांकि, एफपीआई को अभी भी भारतीय बाजारों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके निवेश लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स। पांडेय ने माना कि अधिकांश अधिकार क्षेत्रों में विदेशियों के लिए कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, लेकिन यह मामला सेबी के दायरे में नहीं आता है। भारत में, निवेश पर कर निवेश की अवधि के आधार पर लगाया जाता है। 12 महीने से पहले बुक किए गए लाभ को शॉर्ट टर्म निवेश माना जाता है, जिस पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है, जबकि 12 महीने के बाद बुक किए गए प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म निवेश होते हैं और उन पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है।

प्रक्रिया होगी आसान

पांडेय ने यह भी कहा कि कुछ छोटी जापानी इकाइयों ने न केवल भारत आने, बल्कि वहां लिस्ट होने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे भारत में शोध कार्य करना और एक आरएंडडी सुविधा स्थापित करना चाहते हैं जो सूचीबद्ध हो। अनुमति समयसीमा कम करने का यह प्रयास प्रक्रिया के अधिक डिजिटलीकरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग भी शामिल है। एक बार प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाने के बाद, नियामक समयसीमा को अधिक पारदर्शी तरीके से ट्रैक और गणना करने की योजना बना रहा है। विदेशी निवेशकों की ऑन बोर्डिंग को आसान बनाने के लिए सेबी ने हाल ही में कई पहल की हैं। वर्ष 2025 में, इसने स्वागत-एफआई नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो एफपीआई के लिए रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लेन के समधान के लिए सिंगल-विंडो इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इस प्लेटफॉर्म के साथ, बाजार नियामक का लक्ष्य एफपीआई, बिचौलियों और नियामक के बीच समन्वय में सुधार करना है, ताकि देरी कम हो और एफपीआई रजिस्ट्रेशन और पोस्ट-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता आए। वर्ष 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी से लगभग 35,962 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है। हाई वैल्यूएशन और कमाई में लंबे समय तक मंदी ने विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों से पैसा निकालकर ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे एआई-संचालित बाजारों में लगाने के लिए प्रेरित किया है।

सोने-चांदी के भाव गिरने का इंतजार करने वालों को झटका

नई दिल्ली, एजेंसी। पिछले दिनों भारी गिरावट के दौरान बहुत से लोग इस

मुगालते में रहे कि सोने-चांदी के भाव अभी और गिरेंगे। इस वजह से शादियों वाले घरों में खरीदारी नहीं हो पाई। दाम गिरने का इंतजार करने वालों को आज भी बड़ा झटका लगा है। सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोना 6629 रुपये महंगा हुआ जबकि, चांदी 12573 रुपये उछली। आज सोना बिना जीएसटी 158158 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। जबकि, चांदी 276538 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खुली। जीएसटी समेत सोना आज 162902 रुपये और चांदी 284834 रुपये पर पहुंच गई है। हीं, प्लैटिनम भी 2548 रुपये उछलकर 72672 रुपये पर पहुंच चुका है। लवार को चांदी बिना जीएसटी 263965 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 151529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अभी ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता है सोना-चांदी: सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से अभी 17963 रुपये गिर चुका है। जबकि, चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 109395 रुपये सस्ती हो चुकी है।यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

हालांकि, पिछले हफ्ते की भारी उतार-चढ़ाव ने छोटे निवेशकों को दूर रखा होगा, जो खरीदारों का एक बड़ा हिस्सा हैं।

18 और 22 कैरेट गोल्ड के रेट

22 कैरेट गोल्ड अब 6072 रुपये महंगा होकर 144873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 149219 रुपये है। इसके साथ ही 18 कैरेट गोल्ड में भी 6603 रुपये की अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई है। आज यह 118619 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 122177 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 और 23 कैरेट के रेट्स

14 कैरेट गोल्ड का रेट 3875 रुपये चढ़ा है। आज यह 92522 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 95297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिलेगा। आज 23 कैरेट गोल्ड भी 6603 रुपये उछलकर 157525 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। कीमत अब 162250 रुपये हो गई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में टीडी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ कमोडिटी रणनीतिकार डैनियल घाली के हवाले से बताया है कि कीमती धातुओं में जबरन बिकवाली का दौर संभवत: खत्म हो चुका है।

निवेशकों को पहले ही दिन झटका

48 प्रतिशत मुनाफे के साथ लिस्ट हुआ एक्रेशन नुट्रावेदा आईपीओ

नई दिल्ली, एजेंसी। एक्रेशन नुट्रावेदा आईपीओ शेयर बाजार में आज यानी 4 फरवरी को कमजोर शुरुआत की। कंपनी के शेयर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 191 के भाव पर लिस्ट हुए, जो इसके इश्यू प्राइस 129 से करीब 48 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि, बीएसई पर यह शेयर 155.60 पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से लगभग 4 प्रतिशत नीचे रहा। ग्रे मार्केट में जिस तरह की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद जताई जा रही थी, उसके मुकाबले यह शुरुआत थोड़ी फीकी मानी जा रही है।

अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ तीन दिन में कुल 1.83 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशकों की तरफ से इसे 2.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि एनआईआई कैटेगरी में 2.08 गुना और क्यूआईबी सेगमेंट में 1.01 गुना बोली लगी। कंपनी को कुल 12.80 लाख शेयरों के मुकाबले 23.44 लाख शेयरों के लिए आवेदन मिले। यह आईपीओ 28 से 30 जनवरी के बीच खुला था और 2 फरवरी को इसका अलॉटमेंट फाइनल हुआ।

एक्रेशन नुट्रावेदा, जिसकी स्थापना 2021 में हुई थी, आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्युटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर, ऑयल, क्रीम और जेल जैसे कई फॉर्मेट में प्रोडक्ट

तैयार करती है। यह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर काम करती है और भारत के साथ-साथ श्रीलंका, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में भी कारोबार करती है। आईपीओ से जुटाए गए 24.77 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने, नई यूनिट लगाने, मशीनरी खरीदने और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में करेगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)